

The jurisdiction for the stated subject matter constitutionally lies in exclusivity with the Chairman, Rajya Sabha and, in an eventuality, with the Parliament and Hon'ble President.

Taking note of public domain information and inputs available, it is appropriate that the Secretary General, Rajya Sabha shares this, for information, with the Secretary General, Supreme Court of India.

\$THE UNION BUDGET, 2025-26— Contd.

MR. CHAIRMAN: Now, further discussion on the Union Budget 2025-26. On the 11th February 2025, Shrimati Darshana Singh had not concluded her speech while participating in the discussion. Therefore, I call upon Shrimati Darshana Singh to continue her speech. Now, Shrimati Darshana Singh.

श्रीमती दर्शना सिंह (उत्तर प्रदेश): सर, आपने मुझे इस वर्ष के बजट 2025-26 पर पुनः बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ।

(उपसभापति महोदय पीठासीन हुए।)

महोदय, मैं आपको इस सदन के माध्यम से बताना चाहूंगी कि यह बजट सिर्फ एक वार्षिक बजट नहीं है, बल्कि यह बजट 2047 के विकसित भारत का रोड मैप है, जो 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। यह बजट गरीब कल्याण, युवा, किसान एवं महिला के विकास को समर्पित बजट है।

महोदय, किसान हमारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसलिए समृद्ध समाज के लिए समृद्ध किसान का होना बहुत जरूरी है। महोदय, इस बजट में हमारे देश के अन्नदाता किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड के ऋण की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। इसका लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को मिलेगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के सवा दो करोड़ किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। इससे हमारे किसान भाइयों को जरूरत पड़ने पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा और वह आत्मसम्मान से अपना जीवन जी सकेगा। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी का हमेशा से यह मानना रहा है कि जब देश का किसान समृद्ध और संपन्न होगा, तभी देश उन्नति और विकास की दिशा में सही मायने में आगे बढ़ेगा। इसलिए इस बजट में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जा रही है, जिससे इसका सीधा लाभ देश के लगभग 10 करोड़ किसान भाइयों को होगा।

⁵ Further discussion continued from the 11th February, 2025.

महोदय, जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार उर्वरक उत्पादन में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि इस देश के किसान यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें और पर्याप्त मात्रा में उन्हें यूरिया की सप्लाई हो सके। इस दिशा में सरकार ने कई आवश्यक कदम भी उठाए हैं। सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बंद पड़े तीन यूरिया संयंत्रों को फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिससे किसान भाइयों को पर्याप्त मात्रा में यूरिया मिल सकेगा। असम के नामरूप में यूरिया उत्पादन के लिए एक नया संयंत्र स्थापित किया जाएगा। महोदय, इसके साथ मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि 2014 से पहले - मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से हूँ - मैं बताना चाहूंगी कि एक समय ऐसा था कि जब हमारे किसान भाइयों को यूरिया के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। उनको यूरिया तो नहीं मिलती थी, लेकिन कभी-कभी पुलिस की लाठीचार्ज में उनकी पिटाई जरूर हो जाती थी। इस तरह का जो माहौल था, इससे इस देश के किसानों को निकालने के लिए प्रधान मंत्री जी ने इस तरह की योजनाएँ बनाईं।

महोदय, सरकार ने अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, मध्यम वर्ग की आर्थिक योजना सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उनकी 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री करने का काम किया है, जिससे मध्यम वर्ग के हाथ में पर्याप्त धन होगा। इससे उनकी जो purchasing power है, वह बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

महोदय, इस बजट में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है। अब वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ा कर एक लाख रुपए कर दी गई है। इससे सीनियर सिटिजन को ज्यादा बचत करने में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

महोदय, इस बजट में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के नए अवसर देने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं।...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: माननीया दर्शना जी, आप conclude करिए, आपका समय खत्म हो गया है।

श्रीमती दर्शना सिंह: सर, मैं conclude कर रही हूँ। महोदय, यह बजट युवाओं की शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

महोदय, आज माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयास से भारतीय रेल आम जन को विश्वस्तरीय सुविधाएँ मुहैया करा रही है। इस क्रम में इस बजट में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाईं और चलाई जाएँगी।...(समय की घंटी).... इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी।

महोदय, बस मैं अपनी एक और बात कहते हुए conclude कर रही हूँ। महोदय, माननीया वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी ने लगातार आठवीं बार बजट पेश किया है। मैं इसके लिए माननीया वित्त मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। साथ ही, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ, जिनके नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत के विज़न को मजबूती देने वाला बजट पेश हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। माननीय श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी। आपके पास 15 मिनट्स हैं।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी (महाराष्ट्र): उपसभापति महोदय, आपका धन्यवाद। कवि सुदामा पांडेय 'धूमिल' जी ने कहा था:

एक आदमी रोटी बेलता है,
एक आदमी रोटी खाता है,
एक तीसरा आदमी भी है,
जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है,
वह सिर्फ रोटी से खेलता है।
वह तीसरा आदमी कौन है?
मेरे देश की संसद मौन है।

उपसभापति महोदय, वे भी क्या दिन थे, जब संसद में देश का बजट पेश होता था, तो देश की सड़कें ठहर जाया करती थीं; रेल बजट पेश होता था, तो लोगों की उम्मीदें रेल के डिब्बों की तरह पटरियों पर दौड़ने लगती थीं। पूरा देश धड़कनें रोक कर वित्त मंत्री और रेल मंत्री को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है, मीडिया चैनल्स सरकार का महिमामंडन करती हैं और बेचारी जनता बजट के आँकड़ों के शब्दजाल में उलझी हुई महीनों बाद समझ पाती है कि उसका तो फिर से कट गया।

उपसभापति महोदय, पिछले दो साल अमृतकालीन बजट पेश किए गए और इस बार एक नई शब्दावली गढ़ी गई है - तुष्टिकरण बनाम संतुष्टिकरण का बजट। उपसभापति महोदय, सुनने में कितना अलंकारिक लगता है यह शब्द! सोच रहा हूँ कि देश की वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी से पूछूँ कि आखिर किसकी संतुष्टि! जिस बजट में मनरेगा के लिए एक रुपए की बढ़ोतरी न हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो; जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से एक रुपया भी इजाफा नहीं निकल सका, तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब! इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त! वे, जो महाराष्ट्र में लोक सभा और विधान सभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। क्या उन 40 लाख लोगों में मनरेगा का एक भी मजदूर नहीं था? क्या सारे के सारे 12 लाख की छूट वाले थे, आगे के लोग थे?

उपसभापति महोदय, कल जब वित्त मंत्री जी देश की संसद में भाषण दे रही थीं, तो वहाँ मुम्बई में कोई गरीब इंसान जब अपनी जेब टटोल कर अपनी मोटरसाइकिल में एक लीटर पेट्रोल भरवा रहा था, तो उस पेट्रोल की कीमत थी 103 रुपए प्रति लीटर! आखिर इतना महंगा पेट्रोल-डीजल खरीद कर कौन संतुष्ट हो रहे हैं - इस देश के गरीब लोग या फिर सरकार के चहेते धन्नासेठ?

उपसभापति महोदय, वित्त मंत्री जी इस बजट को मध्यम वर्ग को संतुष्ट करने वाला बजट बता रही हैं। मैडम, हम-आप यहां पर बैठे रहते हैं और वहां बाहर, इसी दिल्ली में, एक लीटर दूध,

चाहे वह 'अमूल' का हो या फिर 'मदर डेरी' का हो, उसकी कीमत 73 रुपये प्रति लीटर है। इसे इतना महंगा दूध बेच करके कौन संतुष्ट हो रहा है - गरीब जनता या आपके धन्नासेठ दोस्त? महोदय, इस सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। चाहे देश में लहसुन 400 रुपये प्रति किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपये प्रति किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदय बजट में महंगाई का 'म' भी नहीं बोलती हैं। ...**(व्यवधान)**... मैं बच्चों की किताब और पेंसिल तक पर टैक्स लगाने वाली सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताते हैं, खुद को धार्मिक कहने वाली सरकार, भगवान श्रीकृष्ण के प्रिय खाद्य पदार्थों, दही और मक्खन तक पर जीएसटी लगाती है और बात करती है - मध्यम वर्ग की हिमायती होने की! जिंदा रहती हुई जनता से हर चीज पर टैक्स वसूलने वाली यह सरकार, कम से कम मरने पर तो लोगों को बख्शा देती, लेकिन नहीं, वहां भी [£] है। अंतिम संस्कार के सामानों, जैसे - अगरबत्ती, धूपबत्ती, केवड़ा जल, चंदन पाउडर, जौ, बताशा, काला तिल, पंचरत्न, कपूर और कफन तक पर टैक्स लेने वाली यह सरकार किस मुंह से खुद को मध्यम वर्ग का हितैषी बताती है? कौन सी संतुष्टि, किसकी संतुष्टि? कदम-कदम पर टैक्स देकर [£] वाली जनता की या फिर जनता से टैक्स वसूल करके धन्नासेठों का खजाना भरने वाली सरकार की - किसकी संतुष्टि हो रही है?

उपसभापति महोदय, 18 अगस्त, 2015, बिहार के आरा का ऐतिहासिक मैदान, सजा हुआ मंच, हजारों की भीड़ और सामने खड़े हुए देश के प्रधानमंत्री का भाषण—बिहार के भाइयों-बहनों आज मैं बिहार के लिए पैकेज की घोषणा कर रहा हूँ। 50 हजार करोड़ कर दूँ कि ज्यादा कर दूँ; 60 हजार करोड़ कर दूँ कि ज्यादा कर दूँ; 70 हजार करोड़ कर दूँ कि ज्यादा कर दूँ; 80 हजार करोड़ कर दूँ कि ज्यादा कर दूँ; चलो, मैं बिहार को सवा लाख करोड़ का पैकेज दे रहा हूँ। महोदय, 10 साल हो गए, लेकिन वही ढाक के तीन पात। बिहार आज भी विकास की बाट जो रहा है। प्रधान मंत्री जी का वह भाषण आज भी Youtube Channel पर सुना जा सकता है।

*जो * बोल के करता है मुतमइन सबको,
वो* बोल के खुद मुतमइन नहीं होता।*

श्री उपसभापति: इमरान जी, आपको * शब्द के बारे में मालूम है। It will not go on record.

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : उपसभापति महोदय, यह तो राहुल जी का असर है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It will not go on record.

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : सर, कौन सा शब्द?

[£] Expunged as ordered by the Chair.

* Not recorded.

श्री उपसभापति : * शब्द को आप जानते हैं।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी : ठीक है, सर।

*जो मिथ्या बोल के करता है मुतमइन सबको,
वह मिथ्या बोल के खुद मुतमइन नहीं होता।*

सर, यह राहुल जी का असर है, जो मखाना बोर्ड की घोषणा हुई। अखिलेश जी, आपको याद होगा कि "भारत जोड़ो न्याय यात्रा" में 30 जनवरी, 2024 को बिहार के पूर्णिया में, रंगभूमि मैदान में राहुल गांधी जी का भाषण था और उसमें उन्होंने मखाना को लेकर आवाज उठाई थी। यह उनका असर है कि आपको मखाना बोर्ड बनाना पड़ा, वरना आप तो मखाना बोर्ड बनाने वाले लोग हैं।

उपसभापति महोदय, बिहार को असत्य पैकेज और चुनावी दिलासे देना बंद करिए। आज भी जब कोसी में बाढ़ आती है, तो पूरा सीमांचल बरबाद हो जाता है। मैंने उस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। 2016-17 की बाढ़ में मैंने अपने इन्हीं हाथों से वहाँ राहत सामग्री बांटी है। अगर सच में आप बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बिहार को बाढ़ से बचाने का प्रबंध करिए। पूर्णिया एयरपोर्ट 10 साल से बाट जोह रहा है। उसके लिए घोषणा 2014 में हुई, लेकिन वह आज तक बन कर तैयार नहीं हुआ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बजट के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी आवाज उठाई थी और आज फिर मैं वित्त मंत्री जी से दामन फैला कर के अनुरोध करना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? यह मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून-पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत!

*रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं,
अपनी आंखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं।*

उपसभापति महोदय, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटकर, मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद कर देना, प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देना, नई मंजिल योजना बंद करना, धरोहर योजना बंद करना.. 2024-25 के बजट में माइनोंरिटी मिनिस्ट्री के लिए 3,183 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन देश को हैरत होगी कि बाद में समीक्षा करके इसको लगभग आधा कर दिया गया, 1,868 करोड़ रुपए कर दिया गया। मेरा तो सरकार से पूछना है कि कौन संतुष्ट हुआ - इस देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट हुआ या आप संतुष्ट हुए? किसका संतुष्टिकरण हुआ है?

उपसभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने ही 1 मार्च, 2018 को जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को मेहमान बना कर इसी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देना चाहता हूँ। कंप्यूटर देने की बात तो छोड़िए, पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रही थी, उसको भी आपने छीन लिया। आपने ऐसा

* Not recorded.

किसको संतुष्ट करने के लिए किया है? हम इस [£] को समझते हैं। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट काटते-काटते एक दिन मिनिस्ट्री को ही बंद कर देना चाहते हैं।

*वो ज़हर देता तो सबकी नज़र में आ जाता
सो ये किया कि हमें वक्त पर दवायें न दीं।*

उपसभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि शायद आपको पता ही नहीं है कि गृहस्थी चलाने वाली एक गृहिणी की मुश्किलें क्या-क्या होती हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब वह किचन में सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डालती है, तो उसके साथ उसके आँसू भी गिरते हैं। उपसभापति महोदय, शायद उन्हें पता भी न हो कि एक छोटी-सी गाड़ी और एक छोटे-से फ्लैट का ईएमआई भरने के बाद इस देश का एक गरीब इंसान जब अपने बच्चों की फीस भरने के बारे में सोचता है, तो उसे कितनी खुशियों का गला घोटना पड़ता है। शायद उनको पता भी नहीं है कि फसल बेच कर बिटिया की शादी का सपना सजाने वाला किसान जब अपनी फसल बरबाद देखता है, तो वह कितनी रातों सो भी नहीं पाता है। उपसभापति महोदय, शायद वे कभी इस पीड़ा को समझ नहीं पाएँगी कि परिवार के किसी एक सदस्य को कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, तो घर और जमीनें गिरवी हो जाती हैं, लेकिन इलाज नहीं हो पाता।

उपसभापति महोदय, इसी देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब-जब देश की करेंसी गिरती है, तब-तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा-सा देश और उसके प्रधान मंत्री गुस्तावो पेट्रो खड़े हैं, जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगा कर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रधान मंत्री जी खड़े हैं, जो बेड़ी और हथकड़ी लगा कर लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।

उपसभापति महोदय, मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूँ, मुझे दो किरदार याद आ रहे हैं - एक तरफ निक्सन के सातवें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही 'नमस्ते ट्रंप' का नारा लगाते हुए प्रधान मंत्री जी खड़े हैं। मेरे कानों में सुषमा स्वराज जी की आवाज गूँज रही है। बहुत कम बोलने वाले डा. मनमोहन सिंह जी ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधान मंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी, तो एक डॉलर 58 रुपए का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है, तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, न प्रधान मंत्री की गरिमा।

उपसभापति महोदय, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को पाँच किलो राशन के लिए कतारों में लगना पड़ता हो, उस देश में यह सरकार 12 लाख रुपए तक के टैक्स न लेने के लिए अपनी पीठ थप-थपा रही है।

*हुकूमत इस क्रदर आवाम पर एहसान करती है
ये आँखें छीनती है और चश्मे दान करती है।*

[£] Expunged as ordered by the Chair.

उपसभापति महोदय, महाराष्ट्र का भिवंडी हो, मालेगाँव हो, इचलकरंजी हो, यूपी का बनारस हो, मऊआईमा हो, मुबारकपुर हो, रांची का छोटा नागपुर हो, बिहार का भागलपुर हो - हर जगह बुनकरों की उम्मीदें तोड़ रही हैं, लेकिन इस सरकार के पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। मुरादाबाद का पीतल उद्योग, कानपुर का चमड़ा उद्योग, सहारनपुर का लकड़ी उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, अलीगढ़ का ताला उद्योग - सब सरकारी प्लानिंग से तबाह हो रहे हैं। इन तमाम के बीच सरकारी सपोर्ट से बस एक उद्योग फल-फूल रहा है - नोएडा का नफरत उद्योग।

उपसभापति महोदय, जिस देश में 40 से 45 परसेंट मेडिकल फैकल्टी की सीट्स खाली हों, वहां बजट में 75,000 नए मेडिकल सीट्स का ऐलान हो रहा है। सरकार बहादुर कम-से-कम इस देश के पढ़े-लिखे युवाओं को तो मूर्ख समझना बंद करिए। 75,000 मेडिकल सीट्स बाद में बनाइएगा, पहले एम्स में जो 2,161 पद खाली पड़े हैं, उनको तो भर दीजिए।

*वो अब तिजारत पहलू निकाल लेता है
मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है।
मैं इसलिए भी तेरे फ़न की क़द्र करता हूँ
तू * बोल के आँसू निकाल लेता है।*

श्री उपसभापति: माननीय सदस्य, आप जो भी असंसदीय शब्द बोल रहे हैं, वह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। * शब्द वगैरह रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: सर, मैं उस शब्द की जगह मिथ्या कर दे रहा हूँ। आप उस शब्द को हटा दीजिएगा।

श्री उपसभापति : इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप इस बात का ध्यान रखें कि ऐसे जो भी शब्द होंगे, वे रिकॉर्ड पर नहीं जाएँगे।

श्री इमरान प्रतापगढ़ी: उपसभापति महोदय, काश यह बजट बीपीएससी के पेपर लीक की शिकायत करने वाले नौजवानों पर बरसती हुई पुलिस की लाठियों के जख्मों पर मरहम लगा पाता। उपसभापति महोदय, पिछले 80 दिन से 70 साल का एक बुजुर्ग एमएसपी की लीगल गारंटी मांगता हुआ आमरण अनशन पर बैठा हुआ है। काश यह बजट किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की टूटती हुई साँसों की पीड़ा सुन पाता। काश यह बजट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दिल्ली, कोटा, पटना, अहमदाबाद, इलाहाबाद जैसे शहरों में किताबों के साथ गल रहे युवाओं के सपनों को जिंदगी दे पाता। काश, यह बजट वंदे भारत के सुनहरे विजुअल्स की बजाय देश की गरीब जनता को कुछ और पैसेंजर ट्रेनें दे पाता; काश, यह बजट सीनियर सिटीजंस को ट्रेन टिकटों में मिलने वाली रियायतें वापस लौटा पाता, जिनको सरकार ने कोविड के नाम पर छीन

* Not recorded.

लिया था; काश, यह बजट किसानों की राह में कीलें नहीं, बल्कि कालीन बिछाने वाला बन पाता; काश, यह बजट सरकारी मालिकों को यह समझा पाता कि नेहरू को कोसने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसके लिए डा. मनमोहन सिंह साहब की अर्थनीति अपनानी पड़ेगी। आप पिछले 11 साल से नेहरू जी को कोस रहे हैं, आखिर कब तक कोसिएगा? थोड़ा पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़िए, तब पता चलेगा कि पंडित नेहरू किस शख्सियत का नाम है। दुनिया का पहला ऐसा राजनेता, जिसने देश की आजादी के लिए अपनी जिंदगी के 3,259 दिन अंग्रेजों की जेल में बिताए। पंडित नेहरू एक ऐसे महान शख्स थे, जिनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू, जिनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित, जिनके बहनोई पंडित रंजीत सीताराम, जिनकी बेटी इंदिरा गांधी, जिनके दामाद फिरोज गांधी, सबने अंग्रेजों से लड़ते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में जेल काटी। आप किस मुंह से उनकी लकीर छोटी करने की बात करते हैं? नहीं कर पाइएगा, सात जन्मों में नहीं कर पाइएगा, क्योंकि:

*जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है,
जिस्म मिट जाने से इंसान नहीं मर जाते,
धड़कनें रुकने से अरमान नहीं मर जाते,
सांसें थम जाने से ऐलान नहीं मर जाते,
जिस्म की मौत कोई मौत नहीं होती है।*

उपसभापति महोदय, मैं आपके सामने खड़ा होकर एक बहुत छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया, तो जीत का जश्न मनाने के लिए वह शहर की सड़कों पर निकला। उसने देखा कि पूरा शहर तो जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर सड़क के किनारे चादर तानकर सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, वह घोड़े से उतरा, उस फकीर के पास गया और उसे सोता देखकर उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने यूनान फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर को देखा और कहा कि शहर जीतना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना तो गधे का काम है!

उपसभापति महोदय, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि गरीब जनता को लात मारना बंद कीजिए। यह अमीरों के लिए बनाया गया बजट है। यह निराशाजनक बजट है। हम अमृत काल, अमृत काल सुनते आ रहे थे, यह अमृत काल इतनी जल्दी समाप्त हो गया कि अब अमृत काल का कोई नाम तक नहीं लेना चाहता है। इसलिए, मैं इस सदन में खड़े होकर देश की वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहता हूँ कि आपने अल्पसंख्यकों के बजट में जो कटौती की है, उसको बहाल कीजिए। आपने मनरेगा को जो स्थिर रखा है, उसका घाटा 9,754 करोड़ है, कम से कम उतना बढ़ा करके फिर से उसे बहाल कीजिए। **...(समय की घंटी)...** नौजवानों को रोजगार दीजिए, किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दीजिए, यही मैं आपसे अपील कर रहा हूँ। सर, आपने मुझे जो इतना समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

श्री बालयोगी उमेशनाथ (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद!

माननीय प्रधान मंत्री जी और राष्ट्रपति जी के बहुत ऊंचे विचार और ऊंची सोच के माध्यम से राष्ट्रपति जी का भाषण बहुत संतुलित और बहुत व्यवस्थित है। भारत की विकास यात्रा और अमृत काल को अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि देश में बहुत लंबे समय से धारा 370 भी चल रही थी और उससे लाखों की तादाद में लोग जूझ रहे थे। इधर, श्रीराम जन्मभूमि, जो पिछले 1,000 साल की समस्या थी, उसका समाधान होने में बहुत विलंब हुआ। उसके लिए 500 साल तक इस देश के ऋषि-मुनियों ने संघर्ष किया और वह संघर्ष का काल पूर्ण हुआ।

महोदय, इस देश में निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत सारे रोड्स बने, कई पुल बने, जिससे अयोध्या तक जाने के लिए लाखों लोगों को खूब सारी सुविधाएं प्राप्त हुईं। माननीय प्रधान मंत्री जी के "किसान सम्मान निधि" के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने लगभग 4 करोड़, 41 हजार रुपये की राशि का भुगतान भी हुआ। 'प्रधानमंत्री आवास योजना' का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया, इसके लिए सरकार ने 5 लाख, 36 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। राष्ट्रपति जी ने इस देश के हित के लिए, चिंतन के लिए निरंतर अपना उद्बोधन देकर पूरे राष्ट्र के लोगों को अभिभूत किया है। बजट में माननीय राष्ट्रपति जी ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को दृष्टिगत रखते हुए उसके विकास की ओर ध्यान दिया है। 'अंत्योदय योजना' की भावनाओं के प्रति सरकार संकल्पित रही है। गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले - एक तरफ पिछले अनेकों वर्षों से हम यह बात सुनते आ रहे थे कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें रोटी, कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन जब से इस देश में माननीय प्रधान मंत्री जी की सरकार आई, तब से सबसे पहले गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान देने का संकल्प लिया गया। अभूतपूर्व व्यवस्थाएं स्थाई रूप से मिलें, इस पर माननीय प्रधान मंत्री जी का पूरा ध्यान केंद्रित रहा है और समाज उससे लाभान्वित भी हुआ है। इन्हीं मूलभूत योजनाओं की वजह से देश में 70 वर्षों के बाद प्रत्येक नागरिक को ऐसा लग रहा है कि चाहे वह गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे जूते पर पालिश करने वाला हो, चाहे भिक्षावृत्ति करने वाला हो, इस देश में माननीय प्रधान मंत्री जी मन, वचन, कर्म से सत्य, धर्म और अहिंसा के साथ चल कर भारत के विकास में हम सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है, वह बहुत ही सराहनीय है।

देश में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए 1,75,000 आयुष्मान मंदिर बने हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि क्या राम मंदिर बनने से इस देश का कल्याण होगा, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आरोग्य मंदिर भी बने हैं, जिनमें लोगों को असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाई जाएगी, चाहे वह कैंसर हो, डायबिटीज हो, टीबी हो, सब रोगों से मुक्ति दिलाई जाएगी। ऐसी व्यवस्थाओं में समाज अग्रणी पंक्ति में आए, उसके लिए यह सरकार निरंतर संकल्पित है। विपक्ष बोलता रहता है कि क्या मंदिर बनाने से भारत का कल्याण होगा? तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत की सरकार चल रही है, तब से भारत में पूर्ण रूप से शांति बनी हुई है। लाखों-करोड़ों लोग डरावनी जिन्दगी से मुक्त हुए हैं। अब कहीं भी बम फटने की सूचना प्राप्त नहीं होती है। धारा 370 के साथ-साथ इस देश में कहीं भी किसी प्रकार की अशांति नहीं हुई है। आज इस देश में सब लोग बहुत अमन और चैन से जी रहे हैं।

माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सभी लोगों के जीवन के लिए ध्यान दिया है, लेकिन कुछ लोग राजनीति से प्रेरित बजट बता रहे हैं, जबकि बजट में सभी बातें ऑर्थेंटिक हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ दिया गया है और उधर माननीय मोदी जी का ऊंचा विचार, ऊंची सोच, और ऊंचा चिंतन — ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास - सभी प्रकार हमें सामाजिक समरसता के रूप में देखने को मिल रहा है और जाति-पाति, पंथ, संप्रदाय को एक तरफ रखकर इस देश में सब लोगों के लिए काम हो रहा है। जो काम 70 वर्षों में नहीं हुए, वे केवल 10 वर्षों में करके दिखाए हैं। श्री राम मंदिर की समस्या, जो कि बहुत पुरानी थी, उसका भी समाधान हुआ है और हमको ऐसा भी लगने लगा कि इस देश की सबसे बड़ी पंचायत, जो राज्यसभा और लोकसभा है, उनमें अनेकों ऋषियों का नाम लिया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी के आने के बाद लोगों के माथे पर तिलक लगा हुआ देखने को मिला है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधे हुए देखने को मिला है और इस देश में सब लोगों को सनातन धर्म की परम्परा के साथ जीने का अधिकार जिस तरह से मिला है, मैं समझता हूँ कि घर-घर सनातन की चर्चा हो रही है।

माननीय राष्ट्रपति जी का ध्यान इस देश के गरीब से लेकर अमीर तक बना हुआ है। उनकी भावनाएं बिल्कुल पवित्र हैं, उनका भाव ऐसा है, जैसे सबरी माता का भाव था, जो राम जी को निरंतर 14 वर्ष तक निहारती रहीं। सबरी के समान ही इस देश की राष्ट्रपति जी हैं। सबरी का भाव त्रिलोकी के नाथ राम जी के प्रति था, ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति जी का भाव इस देश की तमाम जनता की ओर बना हुआ है। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उनको पूर्ण रूप से धन्यवाद के साथ-साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Sasmit Patra.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I stand here today, not just as a representative of my State, Odisha, but as the voice of a State that has been abandoned by this Union Budget. This is not just neglect, but this is an affront to four-and-a-half-crore people of Odisha. Let me remind this House, that the Odisha BJP, in its 2014 election manifesto, promised Special Category Status for Odisha. Eleven years later, where is that promise, where is that status and where is the justice? The Biju Janata Dal and our leader, Naveen Patnaikji, have been constantly demanding Special Category Status for Odisha over the past two decades. The four-and-a-half-crore people of Odisha are hopeful that the State will be provided Special Category Status. It has not happened in this Budget.

Odisha is the economic backbone of this nation. Our coal, our iron ore, our minerals fuel India's progress, yet when Odisha asks for its fair share, this Government turns its back. We suffer cyclones and natural disasters year after year after year, yet Delhi refuses to recognise our pain. This Budget showers favours on some, ignores others and treats Odisha like an afterthought. Is Odisha only good enough to extract minerals, coal and wealth, but not worthy of growth and support for the Special Category Status?

I will conclude. My time is out. In concluding, Odisha's resilience must be rewarded, not overlooked. If we expect our State to rebuild after every catastrophe, while continuing to fuel India's growth, then, we must ensure it receives this support. This Budget must not turn its back on Odisha. This is the decisive moment. Please provide Special Category Status to Odisha through this Budget. *Bande Utkala Janani! Jai Hind!*

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A.D. Singh - not present. Shrimati P.T. Usha - not present. Shri Abdul Wahab - not present. Shrimati Sangeeta Yadav. आपका 5 minute का समय है।

श्रीमती संगीता यादव (उत्तर प्रदेश): उपसभापति महोदय, आपने मुझे भारत को विकसित बनाने वाले बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करती हूँ और आपके माध्यम से सदन को प्रणाम करती हूँ।

सर, मैं यूपी से आती हूँ, तो महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए बधाई देती हूँ और वहाँ पर हुई अप्रिय घटना पर अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त करती हूँ। सर, 2014 से पहले अगर किसी को काशी-विश्वनाथ के दर्शन करने होते थे, तो हम लोगों के पास फोन आता था, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ, तो जाने से भी डर लगता था और अयोध्या के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते थे। आज जो भी महाकुंभ में जा रहे हैं, वे प्रयास कर रहे हैं कि मैं अयोध्या भी चला जाऊँ और काशी-विश्वनाथ के दर्शन भी कर लूँ। अगर यह सब हो पाया है, तो माननीय मोदी जी की वजह से हो पाया है। अभी मैं अपने एक साथी को सुन रही थी, उन्होंने सनातन धर्म पर जो बात कही, वह पूरी चरितार्थ हो रही है।

उपसभापति जी, मैं अभी माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा सुन रही थी और बजट पर अपने विपक्ष के भाई-बहनों को भी सुन रही थी, तो उन्होंने बार-बार एक बात यह कही कि युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया गया, लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी। मैं इस बात पर तथ्यों के माध्यम युवा बजट पर बात करना चाहूँगी। मुझे कहने में गुरेज नहीं कि यह युवा समर्पित बजट है और मैं फैक्ट के माध्यम से बताना चाहूँगी। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप ईको सिस्टम बन चुका है। इसका श्रेय हमारे युवा उद्यमियों को ही जाता है। स्टार्ट-अप इंडिया और स्किल इंडिया कार्यक्रमों ने लाखों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें नए रोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार किया है। आज देश में 1.3 लाख स्टार्ट-अप्स पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें से 115 से अधिक यूनिकॉर्न शामिल हैं। इस बजट में स्टार्ट-अप इंडिया के लिये लोन की जो सीमा थी, वह 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ तक कर दी गई है और गारंटी की फीस भी कम कर दी गई है।

महोदय, 1 करोड़ युवा पीढ़ी के लिए Internship योजना तैयार की गई है। डिजिटल क्रांति से इस युग में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है। महोदय, भारत 5 जी, Artificial Intelligence, Cloud Computing, Blockchain जैसी तकनीकों में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

महोदय, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से 8 लाख नये रोजगारों का सृजन हुआ है, निर्माण के क्षेत्र में भी 20 लाख नये रोजगारों का सृजन हुआ है। बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश के कारण यह संभव हुआ है।

महोदय, एमएसएमई सेक्टर के लिए 25 हजार करोड़ का जो Technology Upgradation Fund तैयार किया गया है, इससे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, उन्हें रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। महोदय, इन्फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले 6 करोड़ मजदूरों को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा गया है, स्टेम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1500 स्कूलों में Robotics और Artificial Intelligence लैब्स की स्थापना की गई है।

माननीय उपसभापति जी, भारत में पहली बार 50 हजार विदेशी छात्रों ने भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया है। यह हमारे देश की उच्च शिक्षा तंत्र की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को दर्शाता है। महोदय, सबसे बड़ी बात, जो मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, वह यह है कि मेरे हज़बैंड भी इन्कम टैक्स विभाग में एडिशनल कमिश्नर हैं। पहले हमारे पास बायो डेटा आते थे कि मैडम, नौकरी के लिए थोड़ा प्रयास कीजिए, यह कीजिए, वह कीजिए। महोदय, हमारे पास ऐसे बहुत बायो डेटाज आते थे। उनके पास दो ही काम होते थे, वे लोग या तो एडमिशन के लिए प्रयास करते थे या नौकरी के लिए, लेकिन आजकल मैंने जो बदलाव देखा है, उसमें मैं यह देख रही हूँ कि जो भी यूथ आ रहा है, वह यह नहीं कहता कि नौकरी चाहिए, बल्कि यह कहता है कि मैडम, कुछ काम करना चाहते हैं, क्या आपकी तरफ से इसमें कुछ मदद हो सकती है? महोदय, सोच का यह जो बदलाव आया है, यह 2014 के बाद माननीय मोदी जी के प्रयासों से आया है और इसकी कोई कीमत नहीं है।

उपसभापति महोदय, मैं देश के अन्नदाता के बारे में भी कुछ बात करना चाहूंगी। महोदय, किसान हमारे अन्नदाता हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी यदि कहीं पर भी कोई बैठक हुई है, पार्टी या संगठन की भी कोई बैठक हुई है, हम सांसदों, माननीय मंत्रियों की बैठक हुई है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे किसान भाइयों की चर्चा न हुई हो, हमारे प्रधान मंत्री जी ने उनकी चर्चा न की हो। महोदय, इस बजट में भी उनकी चर्चा हुई है और मैं अपने कुछ फैक्ट्स के माध्यम से उनके बारे में बताना चाहूंगी। आकांक्षी जिलों की अभूतपूर्व सफलता के बाद 'प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना' सौ जिलों में शुरू की गई है। दलहन पर आत्मनिर्भरता के लिए 'राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन' को कार्यान्वित किया जा रहा है। महोदय, कपास उत्पादन में 5 वर्ष के लिए नये मिशन का आयोजन किया गया है। आज हमारी सरकार तूहर, उड़द, मसूर पर मिशन के साथ 6 वर्षीय दलहन आत्मनिर्भर कार्यक्रम का भी कार्यान्वयन कर रही है।

महोदय, आधुनिक कृषि में तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। सरकार ने कृषि क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन हेतु 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया है। यह निवेश किसानों को उन्नत उपकरणों, सटीक कृषि तकनीकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बेहतर जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

माननीय उपसभापति जी, इसके अलावा सरकार किसानों को Soil Health Cards, फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास कर रही है।

माननीय उपसभापति जी, चूंकि मैं यूपी से आती हूँ, इसलिए यूपी के लिए इस बजट में क्या है, उस पर बात करना चाहूंगी। महोदय, वहाँ पर डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसलिए इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है कि यूपी की हर जगह लगातार चर्चा हो रही है। महोदय, उत्तर प्रदेश को केंद्रीय बजट से 1.5 लाख करोड़ रुपये का आवंटन मिला है। यह राशि राज्य के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा ...**(समय की घंटी)**...

श्री उपसभापति: संगीता जी, अपना भाषण कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती संगीता यादव: महोदय, यही संकट है। मैं जैसे ही खड़ी होती हूँ, वैसे ही समय खत्म हो जाता है।

श्री उपसभापति: संगीता जी, समय मेरे हाथ में नहीं है। अभी बोलने के लिए बहुत स्पीकर्स बचे हैं।

श्रीमती संगीता यादव: ठीक है महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। मैं बस एक मिनट का टाइम ले रही हूँ।

महोदय, 'उड़ान योजना' के तहत यूपी के 24 छोटे हवाई अड्डों को राष्ट्रीय हवाई अड्डों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। महोदय, यूपी में एआई शिक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है, जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी के हब के रूप में विकसित होगा। ...**(समय की घंटी)**... बस, दो लाइनें बोलकर अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। महोदय, महाकुंभ, बौद्ध सर्किट, राम मंदिर के लिए भी इस बजट में धनराशि का प्रावधान किया गया है। मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगी कि मोदी जी और हम सभी का जो एक सपना है कि भारत 2047 तक विकसित देश बने, इस संबंध में मैं सभी से दो लाइनें बोलना चाहूंगी:

*वक्त कम है, जितना दम है लगा दो
कुछ लोगों को हम जगा रहे हैं,
कुछ लोगों को आप जगा दो।*

उपसभापति जी, मुझे अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: संगीता यादव जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मुजीबुल्ला खान जी, आपके पास तीन मिनट हैं, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): सर, मैं बजट के ऊपर बोलना चाहता हूँ, लेकिन हमारे ओडिशा से मेरे साथी सांसद ओडिशा के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं। मैं एक बात बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे बजट में दो लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, वे हैं हमारे देश के किसान और जवान। किसान हम सब का पेट भरता है, हमारी भूख मिटाता है और जवान हमारी रक्षा करता है। इन दोनों के लिए बजट में कुछ नहीं है। तत्कालीन प्रधान मंत्री, लालबहादुर शास्त्री जी

ने "जय जवान जय किसान" का नारा इसलिए नहीं दिया था कि किसान, जो हमारे लिए पैदावार करता है, हमें खाने के लिए अनाज देता है, वह छोटी सी एमएसपी के लिए आज तक स्ट्राइक पर बैठा हुआ है। यह समस्या सारे भारतवर्ष में हर जगह पर है। उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? उन्हें लेकर बजट में कुछ भी नहीं है। अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को full fledged लागू किया जाता, तो यह समस्या नहीं आती। हमारे देश के किसान खुशहाली से रहते और हमें अनाज पैदा करके देते। यह एक सबसे बड़ी समस्या है।

दूसरी बात, हमारे जवान जो सियाचिन जैसे ठंडे क्षेत्र से लेकर गर्म रेगिस्तान तक, हर जगह हमारी रक्षा करते हैं, उन जवानों की बात ठीक से सुनी नहीं जा रही है। इसी कारण, बहुत सी जगहों पर ऐसा होता है कि या तो जवान अपने आपको गोली मार लेता है या फिर सामने वाले को गोली मार देता है। बजट में उनके बारे में भी कोई प्रावधान नहीं है और कुछ कहा भी नहीं गया है।

मैं तीसरी बात रेलवे लाइन के बारे में कहना चाहता हूँ। हमारे ओडिशा में मेरे जिले में एक रेलवे लाइन आने वाली है - जूनागढ़ से नबरंगपुर। उस रेलवे लाइन के लिए बजट में एक रुपया भी नहीं रखा गया है। कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि रेलवे लाइन शुरू होगी, उस पर काम होगा। वह हमारा बैकवर्ड जिला है, आदिवासी जिला है, उस जिले में अभी तक रेलवे लाइन नहीं पहुंची है।

सर, देश को स्वाधीन हुए 75 साल हो गए। बैंकिंग facilities का भी गांव में कोई प्रावधान नहीं है। बहुत से लोगों को पेंशन पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। जो उम्रदराज लोग हैं, वे चल नहीं सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, वे लोग बहुत ही समस्या से आगे बढ़ते हैं। ओडिशा में बहुत सी जगहों पर मोबाइल नेटवर्क भी ठीक नहीं है, जिसके कारण आजकल पढ़ने के लिए जो ऑनलाइन सिस्टम है, उसमें छोटे बच्चे मोबाइल नेटवर्क ढूंढते-ढूंढते कोई पहाड़ पर, तो कोई झाड़ पर चढ़ जाता है। इसे लेकर तत्कालीन मुख्य मंत्री, हमारे नेता, श्री नवीन पटनायक जी ने कई बार केंद्र सरकार से आग्रह किया है। यहाँ तक कि उनकी majority नहीं रहने के बावजूद भी, हमने उन्हें राज्य सभा एमपी की सीट दी थी, जो कि अभी मोबाइल नेटवर्क के मंत्री भी हैं और रेलवे मंत्री भी हैं।...(समय की घंटी)...

श्री उपसभापति: कन्क्लूड कीजिए।

श्री मुजीबुल्ला खान: मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूँगा कि हमारे ओडिशा की रेलवे कनेक्टिविटी और मोबाइल कनेक्टिविटी को ठीक से बहाल किया जाए और प्रावधान किया जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: माननीय मंत्री, श्री रामदास अठावले जी। अनुपस्थिता डा. संगीता बलवन्त जी, आपके पास दस मिनट हैं।

डा. संगीता बलवन्त (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभापति महोदय, आपने मुझे 2025-26 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं अपनी बात का प्रारंभ अपनी स्वरचित पंक्तियों से करना चाहूंगी:

*आधी आबादी ने बजट पेश किया आधी आबादी का
साथ लिया जवान और किसान को
आवाम देख रही है बजट में
मुस्कुराते खिलखिलाते हिंदुस्तान को।*

माननीय उपसभापति महोदय, आज सदन में खड़े होकर अत्यंत प्रसन्नता और गर्व के साथ मैं माननीया वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 की भूरि-भूरि सराहना करती हूँ। यह बजट भारत का 78वाँ बजट है। यह हमारी मोदी सरकार का 12वाँ बजट है और वित्त मंत्री के रूप में माननीय मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसे लगातार आठवीं बार प्रस्तुत किया है। महोदय, भारत का 50.65 लाख करोड़ का यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारी सरकार की नारी सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर युवा, खुशहाल किसान और राष्ट्र के समग्र विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को भारत की विकास यात्रा का केंद्र बिंदु बनाया है। यह बजट इस विश्वास को और मजबूत करता है कि नारी का उद्धार स्वर्णिम युग का द्वार है। इस बजट में कई क्रांतिकारी योजनाएं शामिल की गई हैं, जो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देंगी, स्वास्थ्य और शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करेंगी और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगी।

माननीय उपसभापति महोदय जी, मैं यह कहना चाहती हूँ कि सच्ची प्रगति की नींव आर्थिक सशक्तिकरण है। इस बजट में पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ रुपए तक के टर्म लोन की एक नई योजना शुरू की गई है। एक महिला होने के नाते मैं यह कह सकती हूँ कि जल की उपलब्धता महिलाओं के लिए सम्मान और सुरक्षा है। हमारी सरकार ने 'जल जीवन मिशन' के तहत पहले ही 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किया है, जिससे महिलाओं पर पानी लाने का बोझ कम हुआ है। यह बजट इस योजना को 2028 तक विस्तारित करता है। मोदी सरकार ऐसी अनगिनत एवं विविध योजनाओं और देश हित हेतु लिए गए निर्णयों के कारण जनता में लोकप्रिय है। सरकार देश और जनता के बारे में क्या सोचती है और जनता सरकार के बारे में क्या सोचती है, इसको मैं अपनी पंक्तियों में कहूंगी:

*शीर्ष कदम हो, देश प्रथम हो, सबका हो उद्धार,
देवतुल्य जनता हरदम चाहे मोदी सरकार।*

माननीय उपसभापति महोदय जी, बजट हमारे सरकार की समावेशी विकास, महिला नेतृत्व वाले विकास और भारत के उत्थान के प्रति अडिग प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के गतिशील नेतृत्व में हम सिर्फ महिला सशक्तिकरण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे वास्तविकता में बदल रहे हैं। 'आयुष्मान

भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' का बजट 3,624.80 करोड़ से बढ़ाकर 4,482.90 करोड़ कर दिया गया है, जिससे लाखों महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी।

माननीय उपसभापति महोदय जी, 'प्रधानमंत्री आवास योजना' महिलाओं को घर के स्वामित्व में प्राथमिकता देती है। यह पहल इस बजट में भी जारी है, जो महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और पारिवारिक निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करती है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0' का बजट 1,500 करोड़ से 3,500 करोड़ कर दिया गया है। 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' का बजट 32,500 करोड़ से 54,832 करोड़ कर दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्डों से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अब 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। किसानों के लिए 'प्रधानमंत्री धन्य-धान्य कृषि योजना' चलाई जाएगी। इस योजना से देश के करीब 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी। इसके तहत 100 ऐसे जिलों को कवर किया जाएगा, जहां उत्पादन कम है। तुअर, उड़द, मसूर आदि दालों के लिए 6 साल का स्पेशल मिशन चलाया जाएगा। हमारी सरकार ने टैक्स की सीमा 7 लाख रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 12 लाख रुपये वार्षिक कर दी है। यह अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक कदम है। सरकार का मकसद मिडिल क्लास परिवारों के खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है। जब हर माह एक लाख कमाने वाले व्यक्ति से सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लेगी, तो उस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा बचेगा और जब उसके पास ज्यादा पैसा होगा, तो वह खर्च भी ज्यादा करेगा। इससे मिडिल क्लास परिवारों के खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी और इससे देश की नई अर्थव्यवस्था में एक तेजी दिखाई देगी।

माननीय उपसभापति महोदय, किराए से होने वाली आय पर टीडीएस की सीमा 2,40,000 रुपए से बढ़ा कर 6,00,000 रुपए कर दी गई है। अब किराए से होने वाली 6 लाख की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर दोगुनी छूट मिलेगी। छूट को 50 हजार से बढ़ा कर 1 लाख कर दिया गया है। विकसित भारत के युग में युवा ही हमको लेकर जाएंगे, इसलिए हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा ऐलान युवाओं को लेकर किया है। जब तक युवा तैयार नहीं होंगे, तब तक भारत कभी विकसित नहीं बन पाएगा, सुपर पावर नहीं बन पाएगा। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपए का नया फंड जारी किया है, जिससे नौकरियों के नए अवसर खुलेंगे। माननीय उपसभापति महोदय, जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्कों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50 हजार Atal Tinkering Labs की स्थापना की जाएगी। 23 आईआईटीज़ में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो विगत 10 वर्षों में 65,000 से बढ़ कर 1.35 लाख हो गई है। वर्ष 2014 के पश्चात् शुरू की गई 5 आईआईटीज़ में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा, ताकि 6,500 विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। मोदी सरकार की, एनडीए सरकार की ऐसी तमाम योजनाओं को देखते हुए मेरी कलम ने लिखा:

*सबका साथ सबका विकास की तस्वीर खींच दी,
विकसित भारत की तकदीर खींच दी,
विरासत वाले देखते रह गए,
एक चाय वाले ने बड़ी लकीर खींच दी।*

माननीय उपसभापति महोदय, यह आम बजट बेहद खास बजट है, नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला बजट है। मैं पुनः इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूँ। अंततः दो पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। मैं मोदी सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को देखते हुए कहना चाहूँगी:

*विपक्षियों का सिंहासन हिल गया,
चहुँ ओर कमल ही कमल खिल गया।
मोदी की ऐसी लाजवाब नीतियाँ,
किसी का टूटा घमंड, किसी को ज़ीरो मिल गया।*

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपसभापति: धन्यवाद। माननीय श्री रामजी। आपके पास 5 मिनट हैं।

श्री रामजी (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बजट 2025-26 की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही, मैं अपनी पार्टी की मुखिया, आदरणीया बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, देश में इस बजट से लगभग 70 परसेंट लोगों को निराशा ही हाथ लगी। बजट का देश की जनता बेसब्री से इंतजार करती है कि बजट के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री गरीब जनता को तमाम तरीके की रियायतें देने वाली होगी। टीवी, फ्रिज, खाने वाले सामान, आवश्यक वस्तुएँ, दाल, आटा, चावल, दूध, दही, बच्चों की किताबें, पेंसिल, पेन, कपड़ा, खाद, पेस्टिसाइड, बीज, ये सारी चीजें सस्ती होंगी, पेट्रोल सस्ता होगा। लेकिन जल्दी ही उनको निराशा हाथ लगी, जब माननीया फाइनेंस मिनिस्टर जी गरीबों के लिए इस तरह की कोई भी रियायत नहीं ला पाई।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव) पीठासीन हुईं।]

महोदया, देश में लगभग 70 करोड़ लोग अलग-अलग सेक्टर्स में मजदूरी करते हैं। इनकी मजदूरी 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक होती है और 300 रुपए में एक गरीब व्यक्ति क्या करेगा! इस देश में लंबे अरसे तक कांग्रेस ने भी राज किया और बीजेपी राज कर रही है। इन लोगों ने कहा कि हम गरीबी खत्म करेंगे, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने गरीबी खत्म नहीं की। उनको 300 रुपए आज भी मिलते हैं। 15 साल पहले भी मजदूर को 300 रुपए मिल रहे थे और आज भी मजदूर को 300 रुपए मिलते हैं, लेकिन महँगाई आसमान पर जाती है। मान्यवर, 2011 के Socio Economic and Caste Census के अनुसार, 56 परसेंट ग्रामीण गरीब परिवारों के पास खेती के लिए कोई जमीन उपलब्ध नहीं है। वे लोग सिर्फ खेतिहर मजदूर बन कर अपना जीवनयापन करते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार के पास लगभग 40 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन खाली पड़ी है। अगर सरकार गरीबों और भूमिहीनों को इसमें से दो-दो एकड़ जमीन दे देती है, तो भारत के कम से कम एक करोड़ परिवार, जो भूमिहीन लोग हैं, वे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में जो मिड-डे-मील दिया जाता है, उसमें बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता। सरकार उस फंड को भी बढ़ाने का काम करे। साथ ही, प्राइवेट स्कूलों की फीस और किताबों की price hike हो रही है। वहाँ जो बच्चों की फीस बढ़ाई जा रही है, उसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। इस पर भी माननीया फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ध्यान देने की जरूरत है। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी कहना चाहता हूँ कि SC/ST का जो फंड होता है, वह फंड उनकी डेवलपमेंट पर, उनकी शिक्षा पर, उनके रोजगार पर खर्च होना है, लेकिन तमाम सरकारें उस SC/ST fund को divert करके अन्य मदों में खर्च करती है। इस पर माननीया फाइनेंस मिनिस्टर रोक लगाएं, ताकि जो फंड जिस मद में खर्च होना है, उसी मद में वह खर्च किया जाए। साथ ही, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँ कि लंबे अरसे तक, काफी दिनों से, SC/ST के बच्चों को scholarship टाइम पर नहीं मिल रही है तथा सरकारी स्कूलों के fee structure की वजह से SC/ST के जो तमाम गरीब बच्चे हैं, वे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। अभी कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला है। आईआईटी में देखने को मिला है कि गरीब बच्चे वहाँ पर एडमिशन लेने में असमर्थ रहे। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि SC/ST के गरीब लोगों के जो बच्चे हैं, उनकी फीस को फ्री किया जाए और साथ ही उनका जो scholarship होता है, वह भी सरकार टाइम पर उनको देने का काम करे।

महोदय, इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने इस देश के अंदर रोजगार के लिए और इस देश को आर्थिक शक्ति बनाने के लिए तमाम दस्तावेज लिखे, तमाम तरह के रिसर्च भी दिए और तमाम तरह की किताबें भी लिखीं। बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ने अपने Volume No.3 में यह लिखा है कि देश के अंदर जो कृषि क्षेत्र है, वह सरकार के अधीन रहना चाहिए। उन्होंने उसके साथ ही यह भी कहा कि बीमा क्षेत्र भी राष्ट्रीयकृत होना चाहिए। अगर आप बीमा क्षेत्र का 100 परसेंट प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, तो इस देश को एक बहुत बड़ा जोखिम उठाना पड़ेगा, देश जोखिम की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए मैं माननीया फाइनेंस मिनिस्टर से कहूंगा कि वे इस पर भी पुनर्विचार करें और बाबा साहेब की इस बात को भी ध्यान में रखें।

महोदय, सरकारी कर्मचारी लंबे अरसे से यह मांग करते चले आ रहे हैं कि OPS लागू किया जाए, लेकिन उनको OPS नहीं मिल रहा है। उनके लिए NPS लाया गया, उसके बाद UPS लाया गया, लेकिन सभी लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि OPS को पुनः लागू किया जाए, उस पर कंसिडर किया जाए।

महोदय, मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते कहना चाहता हूँ कि देश में अलग-अलग प्रदेशों की सरकारें हजारों करोड़ रुपये, जो कि टैक्स का पैसा होता है, उसे वे प्रचार में खर्च करती हैं। कहीं टीवी पर खर्च हो रहा है, कहीं hoarding पर खर्च हो रहा है, कहीं अखबारों में खर्च किया जा रहा है। अपने प्रचार-प्रसार के लिए टैक्स का पैसा खर्च किया जा रहा है। उस पर रोक लगाई जाए ...**(समय की घंटी)**... और उस पैसे को इस देश के अंदर शिक्षा पर, गरीब बच्चों की पढ़ाई के ऊपर लगाया जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्य, please conclude करें।

श्री रामजी: यह last point है। यह बहुत important point है।

महोदया, मैं लास्ट में यह कहना चाहता हूँ कि Aviation Sector के अंदर एक तरह से ₹ मची हुई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि Aviation Sector के अंदर उस ₹ को रोकने के लिए, जिस तरह Telecom sector अंदर TRAI (Telecom Regulatory Authority of India) बनाया गया है ...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्य, अन्य सदस्य भी बोलने वाले हैं। इसलिए अब प्लीज समाप्त करें।

श्री रामजी: वैसे ही Aviation Sector के अंदर भी एक TRAI जैसी regulatory body बनाई जाए, जो price hike को रोकने का काम करे, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत!

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्य, श्री मिथलेश कुमार जी।

श्री मिथलेश कुमार (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने आज मुझे बोलने की जो अनुमति दी है, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, हमारे देश की माननीया वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट हमारे सम्माननीय नेता, माननीय प्रधान मंत्री, आदरणीय श्री मोदी जी के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। मैं आज यहां 2025-2026 के दूरदर्शी केंद्रीय बजट के प्रति गहरी प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बजट पूरे देश की आशाओं को लेकर आया है और यह उन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरा है। यह स्पष्ट रूप से 2047 तक 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के प्रति सरकार की अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2.00 P.M.

आदरणीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लाया गया 2025-26 का बजट देश के विकास की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है।

माननीय महोदया, यह बजट गरीब लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों, किसानों सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। यह बजट एक स्थाई भविष्य के लिए है, जो हरित ऊर्जा, हरित विकास, हरित बुनियादी ढांचे और युवाओं के लिए रोजगार को और प्रोत्साहित करेगा। मुझे विश्वास है कि सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली है और यह एनडीए सरकार की आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दृढ़ निश्चित करता है। बजट में कृषि को विकास का प्रमुख घटक मानते हुए उस पर विशेष जोर दिया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर से आता हूँ, जहाँ हमारी पोवायन तहसील में धान, गेहूँ, गन्ना, आलू मुख्य उत्पाद हैं।

₹ Expunged as ordered by the Chair.

वहाँ के किसानों से मेरी बात हुई, वे बहुत खुश हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचाई तथा भंडारण अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार ने 'प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना' की शुरुआत की है। इसी के अंतर्गत जो सोलर पंप है, उससे किसानों को विशेष राहत, माननीय मुख्य मंत्री योगी जी के द्वारा, माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा दी गई है। इसके अतिरिक्त दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष का आत्मनिर्भर मिशन भी घोषित किया गया है। बजट में उच्च उत्पादकता वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन, कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष मिशन और सब्जियों व फलों के लिए एक विशेष कार्यक्रम जैसे कदमों का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी पहल कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त मछली पालन क्षेत्र के लिए 2025-26 के बजट में कुल 2,703.67 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र, Exclusive Economic Zone और हाई सीज में मछली संस्थानों के सतत उपयोग के लिए सक्षम ढांचा स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

माननीय महोदया, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से निवेदन भी करूँगा कि लक्षद्वीप में जिन बोट्स से मछली उत्पादक मछली पकड़ने जाते हैं, वहाँ पर उन बोट्स में प्रयोग होने वाले केरोसिन कई सालों से बंद कर दिया गया है। जिसकी वजह से उनकी बोट्स खड़ी रहती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन है कि वह वहाँ पर केरोसिन उपलब्ध कराने का काम करे। इस पहल के तहत 'प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना' के बजट आवंटन में 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2025-26 के लिए 64 प्रतिशत की अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है।

माननीय महोदया, इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक वेतन भोगी वर्ग को आयकर में राहत प्रदान करना है। इस कदम के तहत एक लाख रुपए प्रति माह तक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कर में छूट दी गई है, जबकि अन्य करदाताओं के कर भार में भी कमी की गई है। माननीय महोदया, इस पहल से उपभोग और निवेश का एक सकारात्मक चक्र प्रारंभ होने की उम्मीद है, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित किया जा सकता है। वर्ष 2025 में इसे 6.4 परसेंट और वित्त वर्ष 2025-26 में 6.3 परसेंट से 6.8 के बीच रहने का अनुमान है।
...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्य, कृपया आप कन्क्लूड करें।

श्री मिथलेश कुमार: माननीय महोदया, मुझे 10 मिनट का समय दिया गया था। मैंने इसकी कई दिनों से तैयारी की है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): अभी तो आपका समय 5 मिनट ही था।

श्री मिथलेश कुमार: माननीय महोदया, मेरा यह अनुरोध है कि इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए।

माननीय महोदया, इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। व्यवसायों के विस्तार और दक्षता में सुधार के लिए एमएसएमई वर्गीकरण की निवेश और टर्नओवर सीमा को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाने में आसानी है। 'प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना' के तहत गरीबों, किसानों, हमारे देहात क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों को काफी फायदा मिलने वाला है। महोदया, वित्त मंत्री जी ने बजट में एससी-एसटी महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू करने की घोषणा की है।...(समय की घंटी)...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्य, आप प्लीज़ conclude करें।

श्री मिथलेश कुमार: महोदया, यह बहुत इंपोर्टेंट है। मैं एससी समाज से आता हूँ, तो मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं तो सोच रहा था कि मैं 10 मिनट बोलूंगा। एससी समाज पूरे देश में बिखरा पड़ा था, कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब से देश के प्रधान मंत्री माननीय मोदी जी बने हैं, तब से एससीज को लगा है कि हमारी भी कोई सरकार है।

महोदया, अगले पाच वर्षों में दो करोड़ तक का जो टर्म लोन होगा, उसके दायरे में 5 लाख महिलाएं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग आएंगे। मैं आपको एक पुरानी बात याद दिलाना चाहता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब अनुसूचित जाति के लोगों को अफवाह फैलाकर ये गुमराह करते थे कि हम तुम्हें 50 परसेंट छूट दे रहे हैं, 50 परसेंट छूट दे रहे हैं, लेकिन छूट मात्र 5,000 रुपये की थी, जिसमें भैंस, बकरी पालन ही वे कर पाते थे। इस तरह, उनको ठगने का काम कांग्रेस की सरकार करती थी। आज हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री जी ने एससी- एसटी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2 करोड़ तक का लोन देने का काम किया।

महोदया, एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने देश में कई स्टेट्स में भ्रमण किया। माननीय प्रधान मंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, जो "आयुष्मान कार्ड" है, वह चलाई गई।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्य, आप प्लीज़ conclude करें।

श्री मिथलेश कुमार: महोदया, मुझे बस एक मिनट दे दीजिए। एक पश्चिमी बंगाल है, जहां आयुष्मान कार्ड को लागू नहीं किया गया है, नल से जल की योजना लागू नहीं की गई है। वहां कांग्रेस की सेकंड पार्ट की पार्टी है, जो कांग्रेस से निकलकर एक अलग पार्टी बनी और उसने गरीबों का दमन किया। ऐसे ही, केरल में भी नल से जल योजना का लाभ नहीं दिया गया।...(समय का घंटी)...

महोदया, अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश भर में सफाई अभियान चलाया, लेकिन दिल्ली की सरकार में सफाई नहीं हुई। मैं दिल्ली की जनता को बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि सफाई के नाम पर, आयुष्मान कार्ड के नाम पर उन्होंने उन

लोगों को बाहर करने का काम किया, जो जनता का खून चूसते थे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री शराब दिया करते थे, लेकिन नालियों की सफाई नहीं करते थे।

अंत में, मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा जो यह लोक महत्व का बजट देश को दिया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): अगले वक्ता, श्री कार्तिकेय शर्मा; not present. श्री बृज लाल जी।

श्री बृज लाल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, आपने मुझे बजट पर बात करने का मौका दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद।

माननीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट में जो कहा है, उसमें प्रथम कृषि है, दूसरा एमएसएमई है, तीसरा निवेश है और चौथा एक्सपोर्ट है। महोदया, आपने मुझे बहुत कम समय दिया है। मैंने अभी देखा कि मेरा 10 मिनट का समय था, जो पहले 6 मिनट हो गया और अब वह 5 मिनट हो गया है। मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे थोड़ा और समय दे दीजिएगा। प्रथम इंजन है - कृषि।

महोदया, कृषि से 60 करोड़ लोग जुड़े हैं। अगर इसमें मजदूरों को भी जोड़ लिया जाए, तो उससे कहीं ज्यादा संख्या होती है। हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत बड़ा रोल है और इसीलिए कृषि को रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसका हमारी जीडीपी में 19 परसेंट का सहयोग होता है। कांग्रेस के समय में कृषि पर ध्यान नहीं दिया गया, उसे नेगलेक्ट किया गया, लेकिन जब मोदी जी आए, तो 2018 में "कृषि सम्मान निधि" योजना लागू हुई। इन लोगों ने 60 वर्षों तक शासन किया, लेकिन कुछ क्यों नहीं किया? महोदया, यह केवल 6,000 रुपये की बात नहीं है। इस 6,000 रुपये से इस देश का दलित, आदिवासी भूमिहीन होने से बच गया। उसके पास 5 बिस्वा जमीन थी, 10 बिस्वा जमीन है, लेकिन वह खेती नहीं कर पाता था, अगर वह कर पाता था तो केवल मजदूरी कर पाता था। लोग कहते थे कि तुम इस जमीन का क्या करेगा? अब उसको उस 5 बिस्वा जमीन पर 6,000 रुपये मिलते हैं, जिसको वह पैदा नहीं कर सकता था।

महोदया, हमारे राज्य उत्तर प्रदेश में 2004 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तो उसने एक बिल मूव किया और कहा कि दलित की जमीन बेचने में डीएम के परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। उस परमिशन की जरूरत क्यों थी? उस परमिशन की जरूरत इसलिए थी, ताकि दबंग लोग दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की जमीन खरीद न लें। उसके बाद, उसका इतना विरोध हुआ कि वह बिल समाजवादी पार्टी सरकार पास नहीं करा पाई, अदरवाइज़ आज वे सब भूमिहीन हो गए होते। यह जो 6,000 रुपये की सहायता है, इस 6,000 रुपये की सम्मान निधि ने उनको भूमिहीन होने से बचा लिया।

महोदया, इसके बाद, कृषि के लिए यूरिया में हम लोग आत्मनिर्भर हैं। अभी नामरूप में एक यूरिया प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है। हमारे प्रदेश के गोरखपुर में एक फैक्ट्री थी, जो 1968 में लगी और 1990 में बंद हो गई। उसको मोदी जी ने दोबारा शुरू किया और आज वह दोबारा उत्पादन कर कर रही है। इस तरह से कृषि को तमाम सुविधाएं दी गई। आज हमारा

किसान कृषि के क्षेत्र में खुशहाल हुआ है। महोदया, मोदी जी के प्रयास से 75th जनरल असेम्बली ने वर्ष 2024 को 'इंटरनेशनल ईयर ऑफ़ मिलेट' घोषित किया। मिलेट वह फूड है, जिसमें सांवा, कोदो, मडुआ, काकुन, ज्वार, बाजरा आदि गरीबों का खाना होता था, आज वह मिलेट सुपर फूड हो गया है और सुपर फूड को पैदा करने का काम सबसे ज्यादा एरिड एरिया में होता है, जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, कम हैं, तो आज उनके पास मिलेट जैसा सुपर फूड है, मार्केट में इसकी सबसे बड़ी कीमत है।

उपसभाध्यक्ष महोदया, हम 38.4 परसेंट मिलेट पैदा करते हैं, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब कांग्रेस के बारे में बताता हूँ। वर्ष 1954 में कांग्रेस PL480 लाई थी। वह लाल गेहूं था। महोदया, अभी हमारे दीपक प्रकाश जी कह रहे थे कि झारखंड में गरीबी इतनी है कि लोग कटहल का बीज खाते हैं। आप तो उसी क्षेत्र की रहने वाली हैं। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में लोग गोबरैला अनाज खाते थे। जब बैल दवाई खा लेता था, फिर उसके गोबर से जो साबुत अनाज निकलता था, उत्तर प्रदेश में लोग उसको धोकर खाते थे, यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। कांग्रेस के ज़माने में गोबरैला अनाज, साखू के बीज आदि तमाम चीज़ें लोग खाते थे। महोदया, पीएल 480 वर्ष 1969 तक जारी रहा। अमेरिका चड्डी गाढ़ता था, वह कहता था कि तुमको अनाज नहीं देंगे।

आज इतना अनाज पैदा हो रहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और दुनिया का पेट भरने की क्षमता हमारी है। महोदया, कांग्रेस के उस PL480 की एक सौगात अभी बाकी है और वह सौगात है - कांग्रेस ग्रास - पार्थनियम, जो पूरे देश में उगता है, उससे अस्थमा पैदा होता है, एलर्जी पैदा होती है। कांग्रेस के PL480 की सौगात आज भी बीमारी के रूप में प्रसिद्ध है। कांग्रेस ने किसानों के साथ यह किया।

महोदया, दलहन ग्रामीण क्षेत्र में और हर क्षेत्र में प्रोटीन का सबसे मुख्य साधन है, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। हमारा उत्तर प्रदेश दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। योगी जी की सरकार में दलहन का उत्पादन 37 परसेंट बढ़ा है। मध्य प्रदेश में भी बढ़ा है।...(समय की घंटी)... महोदया, मैं तीन मिनट का समय और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्य, प्लीज़ conclude कीजिए।

श्री बृजलाल: यह हाल है कि आज हमारा बुंदेलखंड सबसे ज्यादा — जिसे हम दाल का कटोरा कहेंगे, वहां सिंचाई के साधन नहीं थे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब बेतवा और केन नदी के लिंक की शुरुआत की, उसको मोदी जी ने पूरा किया और आज बुंदेलखंड में जब से सिंचाई की सुविधा हुई है, आज वह धन-धान्य से भर गया है। वहां डिफेंस कॉरिडोर भी है। एक समय तब था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वहीं आज हम दाल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, खाद्य में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वे लोग [£] पैदा करते थे। चम्बल और पाठा जैसे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सरकार इसलिए [£] पालती थी, क्योंकि वे तय करते थे कि किसको वोट देना है। वे [£] पैदा

[£] Expunged as ordered by the Chair.

करते थे और उन्हीं[‡] को परिवारजनों को - एक बांदा का ...(समय की घंटी)... उस समय मैं ही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर था, वह मारा गया। महोदया, मैं दो मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्य, प्लीज 30 सेकंड में conclude कीजिए।

श्री वृजलाल: समाजवादी पार्टी ने उसके भाई को संसद सदस्य बनाया और भाई-भतीजों को एमएलए बनाया, तो मेरा कहना है कि उस समय की सरकारें[‡] पैदा करती थीं और हम विकास की चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन लिमिटेड समय है। मैं इस बजट का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूँ। यह बजट वर्ष 2047 के पूर्ण 'विकसित भारत' का रोड मैप है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): श्रीमती महुआ माजी, आपके पास 5 मिनट बोलने का समय है।

श्रीमती महुआ माजी (झारखंड): महोदया, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा समय चाहिए, क्योंकि आपने इधर भी लोगों को समय दिया है। मैं झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 ने व्यापक आलोचना को भी जन्म दिया है। केंद्र सरकार के सबका साथ, सबका विकास के दावे के बावजूद बजट भाजपा शासित राज्यों का पक्ष लेता हुआ और झारखंड जैसे विपक्ष शासित राज्यों में योजनाओं और परियोजनाओं के आवंटन में भेदभाव करता हुआ साफ प्रतीत होता है। झारखंड भारत में सबसे समृद्ध संसाधन युक्त राज्यों में से एक हैं, जो कोयला, आयरन-ओर और अन्य खनिजों के विशाल भंडार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बावजूद इस बजट में राज्य की बड़े पैमाने पर अनदेखी की गई है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपये देने थे, तो हमारे माननीय मुख्य मंत्री हेमन्त सोरेन जी द्वारा बार-बार पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वह पैसा नहीं दिया गया है और इस बजट में भी उसका कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है। जबकि उस पैसे से हमारे राज्य में बहुत काम हो सकते हैं। माननीय हेमन्त सोरेन जी का अपने समृद्ध राज्य को देश का नंबर वन राज्य बनाने का सपना है, वह भी पूरा हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उस राशि का भुगतान कर दिया जाए। झारखंड में धनबाद में आप जानते होंगे कि झरिया में जमीन के नीचे सालों से कोयले पर आग लगी हुई है, उसके लिए मुझे लगता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी एक बजट होना चाहिए। बरकट्टा, झरिया, जहां देश का बहुमूल्य कोयला जलकर राख हो रहा है, पॉल्युशन हो रहा है, लोग वहां से माइग्रेट कर रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली है, तो पूरे देश में दिल्ली के पॉल्युशन की चर्चा हो रही है, मुझे लगता है कि इसके लिए भी अलग से डिजास्टर

[‡] Expunged as ordered by the Chair.

मैनेजमेंट बजट एलोकेट होना चाहिए। गरीब जनता का सहारा में डूबे पैसों को वापस दिलाने में केन्द्र सरकार झारखंड राज्य को बिल्कुल मदद नहीं कर रही है। सहारा ने न जाने कितने गरीबों को बेसहारा कर दिया है। सहारा में झारखंड के लोगों के लगभग 2,500 करोड़ रुपये की राशि डूबने की आशंका है। तीन लाख से ज्यादा छोटे-बड़े निवेशकों का पैसा फंसे होने का अनुमान है। धनबाद के लगभग 1,872 लोगों ने राज्य सरकार से शिकायत की है और राज्य सरकार लगातार केन्द्रीय रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर पैसे वापस दिलाने की मांग कर रही है, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद केन्द्र सरकार मौन है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

सर, जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड को 2 लाख, 11 हजार, 422 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन जनवरी, 2025 तक केन्द्र सरकार द्वारा केवल 29 हजार, 517 करोड़ रुपये ही दिए गए हैं यानी स्वीकृत राशि का 14 प्रतिशत ही जारी किया गया है। हमारे राज्य में कई ऐसे इलाके हैं, जहां जल की भयानक समस्या है, उसकी किल्लत है, हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड का एक विधान सभा क्षेत्र गाण्डे है, जो बिहार से सटा हुआ है। पिछले साल मई के महीने में वहां गई थी, तो मैंने देखा कि गांव के एक व्यक्ति ने कहा कि उसने दस दिन से स्नान नहीं किया था। वहां पर जितने भी जल स्रोत हैं, वे सभी सूख चुके हैं। वहां नल, कुंआ कोई भी काम नहीं कर रहा है। इसलिए जल-जीवन मिशन के लिए जो स्वीकृत राशि है, वह अविलंब हमारे राज्य को दी जाए। एनसीआरबी का 2022 का डेटा देखें, तो भारत में आत्महत्या दर 12.4 प्रति एक लाख के साथ दुनिया में सबसे अधिक है और मानसिक विकारों का इलाज प्राप्त करने में 83 प्रतिशत की कमी है, जो चिंताजनक है। इसके बावजूद मानसिक स्वास्थ्य को पर्याप्त वित्तीय समर्थन नहीं मिला। युवाओं और छात्रों में डिप्रेशन और आत्महत्या खत्म करने के लिए व्यापक स्वास्थ्य नीति और बड़े बजट की आवश्यकता है। झारखंड में रांची स्थित सीआईपी भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थानों में से एक है, लेकिन इस वर्ष के बजट में इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। यह संस्थान अपने वातावरण और जलवायु परिस्थितियों की वजह से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आदर्श माना जाता है, फिर भी केन्द्र सरकार इसकी उपेक्षा कर रही है। आपको पता होगा कि तेजपुर स्थित LGBRIMH को करोड़ों रुपये आवंटित किए गए हैं, वहीं सीआईपी रांची की उपेक्षा की गई है। यह मानसिक स्वास्थ्य सेवा संसाधनों के असमान वितरण पर गंभीर सवाल खड़ा करता है और गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ पक्षपात करने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस बार के बजट में ऐसा प्रस्तावित है कि प्रधान मंत्री इंटरनेशनल योजना, 2024 के तहत भारत सरकार देश की प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को इंटरनेशनल प्रदान करेगी। इंटरनेशनल के दौरान युवाओं को 5,000 प्रतिमाह का भत्ता मिलने की बात कही गई है, जिसमें 4,500 रुपये प्रतिमाह सरकार देगी और 500 रुपये प्रतिमाह कंपनी अपनी तरफ से देगी। यहां इस बात की तरफ ध्यान दिया जाना जरूरी है कि 500 रुपये प्रतिमाह जो कंपनी देगी, वह उनके पूर्व निर्धारित सीएसआर से जाएगा, यानी इस तरह अगले पांच वर्षों में अपने सीएसआर के मद में सीधे-सीधे 500 करोड़ रुपये की कटौती कर दी जाएगी। ...**(समय की घंटी)**... यह योजना पहले से चल रहे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटीज की कीमत पर भाजपा सरकार का अपना विज्ञापन है। इस तरह शेष 4,500 रुपये प्रतिमाह किस मद से देने वाली है, यह भी स्पष्ट नहीं है। यह बहुत संभव है किसी पूर्व निर्धारित बजट का डायवर्जन है। अतः इस स्तर पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी

चाहिए और इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस इलाके में कंपनियाँ काम करती हैं, वहाँ के पॉल्यूशन से निपटने की जिम्मेदारी कंपनियाँ उठाती हैं। project-affected area में CSR fund का इस्तेमाल art, culture, education, sports, women empowerment, गरीबी उन्मूलन, local infrastructure development जैसी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं के लिए किया जाता है, जिन्हें सरकार अपनी तरफ से internship मद में से खर्च करने के लिए बाध्य कर रही है। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्या, कृपया कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती महुआ माजी: बस, दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। महोदया, कोई job guarantee नहीं है। जैसा कि मुझे मेरे सवाल के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा था, ऐसे में हो सकता है कि युवा बाद में नौकरी के लिए बाहर चले जाएं और स्थानीय लोगों को ...**(समय की घंटी)**... मिलने वाले लाभ भी न मिलें। कहीं ऐसा न हो कि 6 महीने में ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्या, कृपया कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती महुआ माजी: महोदया, 6 महीने से साल भर तक ट्रेनिंग प्राप्त युवा अग्निवीर से बहाल हुए युवाओं की तरह ठगा सा महसूस करें। महोदया, अग्निवीर में तो फिर भी तीन साल की नौकरी है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): माननीय सदस्या, कृपया कन्क्लूड कीजिए।

श्रीमती महुआ माजी: महोदया, मैं बस दो पंक्तियाँ बोलकर अपनी बात खत्म कर रही हूँ। किसी ने ठीक ही कहा है कि:

*वादों की गठरी उठाए फिरते हैं
हक की बातों को दबाए फिरते हैं।
रोजगार के नाम पर मिलती है तालीम
और सपनों को बहलाए फिरते हैं।*

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती संगीता यादव): धन्यवाद माननीय सदस्या। श्री सतनाम सिंह संधू, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

श्री सतनाम सिंह संधू (नाम निर्देशित): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम, मुझे इस सदन में एक साल पूरा हो गया है। इस बजट सेशन में मुझे दूसरी बार बोलने का समय मिला है। महोदया, मैंने 15 मिनट की तैयारी की थी, मुझे 10 मिनट का अंदाजा था, लेकिन पाँच मिनट ही मिले हैं, सभी का समय कटा है। महोदया, शेरों शायरी का माहौल भी है, इसलिए मैं एक शेर अपनी लीडरशिप के धन्यवाद के लिए बोलना चाहूँगा कि:

*हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले,
बहुत निकले अरमा मेरे मगर फिर भी कम निकले, कम निकले।*

महोदया, मुझे बजट पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अब तक के सबसे इंकलूसिव बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। यह बजट सिर्फ एक फाइनेंशियल दस्तावेज नहीं, बल्कि हमारे सर्वोच्च नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन डॉक्यूमेंट है। मैडम, मैं शिक्षा क्षेत्र से आता हूँ और ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब एलिमेंट्री या स्कूल एजुकेशन को 61 परसेंट बजट एलोकेट किया गया है। मैं समझता हूँ कि इससे भारत के फ्यूचर की नींव मजबूत होगी और विकसित भारत और तेजी से विकसित भारत बनेगा। मैडम, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की टॉप पोजीशन पर भारतीय प्रतिभाएं विराजमान हैं, ज्यादातर टॉप इंडस्ट्री लीडर्स, आइआईटीज़ और हमारी भारतीय संस्थानों के अल्युमिनाई हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने तकनीकी शिक्षा के नए सूरज को उगाने का संकल्प लिया है। पिछले 10 वर्षों में आईआईटीज़ में छात्रों की संख्या 100% बढ़कर 1 लाख, 35,000 हो गई है। यही वे नवाचार के बीज हैं जो भविष्य में कटिंग एज रिसर्च को जन्म देंगे और भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर अग्रसर करेंगे। महोदया, आज गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, जब भारत को ग्लोबल एआई समिट पेरिस का सह अध्यक्ष बनाया जाता है। हमने देखा, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने मोदी जी के विजन को न केवल स्वीकारा, बल्कि दुनिया को उससे सीख लेने के लिए भी कहा। यह गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी आज ग्लोबल एआई समिट की प्रेसिडेंसी भारत लेकर आ रहे हैं। तीन एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की सफलता के बाद अब 500 करोड़ की लागत से एक और अनूठा एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है, जो शिक्षा जगत में एआई ड्रिवन पर्सनलाइज्ड लर्निंग को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा। मैडम, आज पूरी दुनिया की नजर भारत की प्रगति पर है, लेकिन इन दिनों भारत दुनिया के सबसे विशाल समागम कुंभ की वजह से ज्यादा चर्चा में है। देश में महाकुंभ का विशाल अयोजन हो रहा है। देश दुनिया से 40 करोड़ लोग पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे हैं। इसमें से 15 लाख से ज्यादा तो विदेशी है। कुछ लोग इतने बड़े पर्व को एक इकोनॉमिक चश्मे से भी देखते हैं। उनका अनुमान है कि महाकुंभ से सवा तीन लाख करोड़ की कमाई होगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारा देश सिर्फ आर्थिकी से नहीं चलता, हमारा देश आस्था से भी चलता है।

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA) *in the Chair.*]

उपसभाध्यक्ष जी, जिस पवित्र जल को हम अमृत समझ कर डुबकी लगाते हैं, दुख की बात है कि कुछ लोग उसे गंदा पानी कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि उससे पाप नहीं धुलते या गरीबी नहीं मिटती। ऐसा कहना महाकुंभ में आए केवल 40 करोड़ श्रद्धालुओं के मन को ही ठेस नहीं पहुंचाता, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों को भी दुखी करता है। जब आस्था का मजाक उड़ाया जाए, तो दिल दुखता है और जब मजाक उड़ाने वाले लोग इसी सदन में बैठे हों, तो दुख के साथ निराशा भी होती है। डिप्टी चेयरमैन साहब, इसके लिए जितनी भी सफायाइयां दी जाएं, पर ये पाप धुलने

वाले नहीं। इतिहास गवाह है कि जब-जब आस्था आहत हुई है, तब-तब बड़े नुकसान हुए हैं और देश कमजोर हुआ है। मैं पंजाब से आता हूँ और पंजाब के एक बहुत ही संजीदा शायर सुरजीत पातर जी की कुछ लाइनें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पातर साहब ने लिखा है — * “If I say something, darkness(evil) won't be able to tolerate it, but if I remain silent, what will the light (Goodness) say?” सर, मैं पंजाब से आता हूँ और हमारी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र श्री हरिमंदिर साहिब है।...(समय की घंटी)... इसके चार दरवाजे सब धर्मों का सम्मान करते हैं। यहाँ पर हर भक्त के भले की अरदास होती है, लेकिन इस पवित्र स्थान पर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में सैनिक-फौज भेजते हुए, टैंकों, तोपों के साथ हमला किया गया। इसके साथ ही, पवित्र सरोवर को निर्दोष लोगों के खून से लाल कर दिया गया।...(समय की घंटी)... इसे सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के चश्मे से देखा गया।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): इसका बजट से कोई मतलब नहीं है।...(व्यवधान)...

श्री सतनाम सिंह संधू: अगर इसको आस्था से देखा जाता, तो यह न होता।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): एक मिनट सुनिए।...(व्यवधान)... बहुत सारे स्पीकर्स हैं और यह भी है कि इसे जल्दी-जल्दी खत्म करना है।...(व्यवधान)... माननीय वित्त मंत्री जी आ जाएंगी, तो हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले सकते हैं।

श्री सतनाम सिंह संधू: अंदाज़ा है कि इस हमले में 25,000 से ज्यादा नौजवानों को घरों से उठा लिया गया और वे लापता हो गए।...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): अगली स्पीकर श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार।...(व्यवधान)... आप ये बात बोल रहे हैं?...(व्यवधान)... आप बोलिए, आपका माइक ऑन है।

श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार (महाराष्ट्र): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपनी तथा अपनी पार्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेस की तरफ से माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत जनरल बजट का स्वागत तथा समर्थन करती हूँ। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को लगातार आठवें बजट के लिए बधाई देती हूँ। मैं इस बजट में किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्यमियों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी की सराहना करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि यह बजट सभी को विकास के अवसर प्रदान करेगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी और राज्यसभा के सम्मानित सदस्यगण, मैं आज आपके समक्ष जिम्मेदारी और विनम्रता की गहरी भावना के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं इस प्रतिष्ठित सदन में

* English translation of the original speech delivered in Punjabi.

अपना पहला भाषण दे रही हूँ। मेरे लिए यह गर्व की बात है कि मैं आप सबके सामने अपनी बात रख रही हूँ।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, देश के प्रधान मंत्री, माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए सरकार ने पूरे विश्व को एहसास दिलाया है कि भारत एक शक्तिशाली देश है। आज पूरा विश्व नए भारत की नई उड़ान के इस अमृत काल का सामना कर रहा है।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जन-भावनाओं का ख्याल रखते हुए बहुत शानदार बजट पेश किया है। यह एक ड्रीम बजट है, जो नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त बनाकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत प्रदान करता है। कर छूट में वृद्धि ऐतिहासिक है। इससे क्रय शक्ति बढ़ेगी, माँग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। निश्चित रूप से, इस बजट से हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज हम विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, यह बजट बाजारों को ऊर्जा देगा, क्रय शक्ति बढ़ाएगा और रोजगार सृजन करेगा। विशेष रूप से, एमएसएमई क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगा। इस बजट में प्रधान मंत्री अनाज उत्पादन योजना के तहत, 100 जिलों में कृषि उत्पादकता, भंडारण सुविधा, सिंचाई और ऋण सेवाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पहल से महाराष्ट्र को बहुत लाभ मिलने की उम्मीद है। कपास और दालों के उत्पादन को बढ़ाने संबंधी निर्णयों से भी राज्य को लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने के निर्णय का मैं स्वागत करती हूँ। इससे निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा।

मुझे उम्मीद है कि पुणे जिला भी इन 100 जिलों में शामिल किया जाएगा। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ यह बजट नए व्यवसायों के विकास को गति देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा। मैं बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर नई नीति रूपरेखा और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण योजना को जारी रखने का स्वागत करती हूँ। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं निजी निवेश को आकर्षित करेंगी और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। महोदय, यह बजट दीर्घकालिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देता है तथा कृषि स्टार्टअप्स और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है। यह बजट निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में महाराष्ट्र की प्रगति को मजबूत करेगा और मुझे उम्मीद है कि माननीय श्री देवेन्द्र जी फडणवीस, माननीय श्री अजित पवार और श्री माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र देश की प्रगति में अग्रणी राज्य बनेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, इस बजट में 52 प्रमुख पर्यटन स्थलों को विकसित करने की नीति की भी घोषणा की गई है। यह पहल देश को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि माननीय श्री फडणवीस जी, माननीय श्री पवार जी और माननीय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र भारत को विकसित राष्ट्र और आर्थिक महाशक्ति बनाने के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों का पूरा समर्थन करेगा। इस इस बजट में सरकार ने उड़ान योजना को 120 स्थानों पर लागू करने का लक्ष्य रखा है। **...(समय का घंटी)...** इसमें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के

निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पुरंदर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। इससे क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा।

उपसभाध्यक्ष जी, दूषित जल सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम है। यह जीवन की गुणवत्ता और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों को खतरे में डालता है। पुणे में मुला मुथा नदी प्रदूषण के लिए सबसे संवेदनशील जल निकायों में से एक है। जयकांथन योजना के तहत मुला मुथा नदी संरक्षण के लिए 230 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। मुझे आशा है कि इससे मुला-मुथा नदी को साफ करने में मदद मिलेगी। पुणे में यातायात की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। ...**(समय की घंटी)**... इस समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परिवहन सुधार की जरूरत है। इस बजट में पुणे मेट्रो के लिए 837 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे मेट्रो निर्माण में तेजी आएगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): सुनेत्रा जी, समाप्त कीजिए, क्योंकि वित्त मंत्री जी आ जाएंगी, और अभी बहुत से वक्ता हैं बोलने के लिए।

श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार: साथ ही इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आस-पास के शहरों का विकास जरूर होगा। लिफ्ट सिंचाई योजनाओं से कृषि उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार जल संकट वाले क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कर रही हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): धन्यवाद।

श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार: इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऊर्जा संरक्षण और लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए 186.44 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। माननीय, मैं माननीया वित्त मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस राशि को बढ़ाया जाए, ताकि कृषि सिंचाई में सुधार हो सके। उपसभाध्यक्ष जी, विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित राज्यों का होना बहुत जरूरी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): धन्यवाद मैडम। भुबनेश्वर कालिता जी। ...**(व्यवधान)**... वित्त मंत्री जी आने वाली हैं, इसलिए जल्दी खत्म करना है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार: महाराष्ट्र में पहले ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं अपर्याप्त थीं, लेकिन अब इसमें काफी प्रगति हुई है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): आप सबके वकील क्यों बन रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... सबके वकील मत बनिए। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार: महाराष्ट्र सरकार द्वारा कई सड़क विकास योजनाएं चल रही हैं। इस बजट में महाराष्ट्र में ग्रामीण परिवहन को बेहतर बनाने में 683.51 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि को और बढ़ाने की जरूरत है।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): धन्यवाद, मैडम। भुबनेश्वर कालिता जी।

श्रीमती सुनेत्रा अजीत पवार: मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से इस राशि को बढ़ाने का अनुरोध करती हूँ। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार विभिन्न बुनियादी ढांचे और विकास परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए पूर्ण समर्थन प्रदान करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ।

SHRI BHUBANESWAR KALITA (Assam): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to begin with my observation on the comment made by one of the senior Members in the Opposition. The hon. Member said, "This Budget does not have a philosophy; this Budget does not have a policy". Sir, I want to start by saying that this Budget does have a philosophy of recognizing the last man in the line and last village in the country. So, development of the last man, development of the last village, and, to begin the development with last village is the philosophy of this Budget.

Sir, if we talk about the policy, there may be differences between the Opposition and the Ruling Party. This point has been elaborated very clearly by our Prime Minister, Shri Narendra Modi, himself. He said and I quote, "I say it with lot of pride. For five to six decades, there was no alternative model for the people. There was only one model. After a long time, after 2014, the country got to witness a new model." So, it is a new model. It is a new philosophy. It is a new policy. They might differ on that. He further said, "We adopted the approach of saturation. The schemes should be delivered 100 per cent. No one should be deprived and pushed towards hopelessness. In the past decade, at every level, we have tried to implement 'Sabka Saath, Sabka Vikas'." That is the philosophy and that is the policy of this Government.

As I have already said, this is the roadmap to achieve the goal of a *Viksit Bharat*, that is, making India a developed nation. Having been an under-developed country, we have suffered a lot but now the country's aim is to become a developed nation, encompassing zero poverty, hundred percent good quality school education, access to high quality affordable and comprehensive health care, hundred percent skilled labour with meaningful employment, 70 percent women participation in economic activities and farmers making our country the food basket of the world. So, this is the roadmap through which the country wants to achieve its goal of being a *Viksit Bharat*. Sir, the Union Budget 2025-26 aims at setting pace for *Viksit Bharat*. The Budget acknowledges that the strength of a country lies in the people, not in the soil, and, thus reinvigorates the Modi Government's commitment to 'Sabka Saath, Sabka Vikas'. Sir, this Budget is holistic. This Budget has a multipronged strategy for

accelerating growth, securing inclusive development, enhancing spending power of the India's middle class, invigorating private sector investments and uplifting household sentiments.

Sir, empowering middle class for a better tomorrow means that the income up to 12 lakhs of rupees would be exempt from income tax as against 7 lakhs of rupees till now, and more money in the hands of middle class means more spending. Globally, the manufacturing industry is a major job provider. Thanks to the efforts of the Narendra Modi Government, growth in the sector has picked up in recent years. According to annual survey of industries... *...(Time-bell rings)*... Sir, I think, I still have some time left.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): The problem is that still 19 speakers are left. Hon. Finance Minister will be here shortly. So, we have to finish it as quickly as possible.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, please give me two minutes to speak about my own State, Assam and the North East. Sir, Assam has earned the distinction of being at rank one in the nation for achieving hundred per cent Direct Benefit Transfer under the National Social Assistance Programme. The major milestone was the laying of foundation stone of Tata Group's Rs. 27,000 crore semiconductor facility at Jagiroad, promising 15,000 direct jobs, supporting 70 ancillary units. Assam's effort to attract mega investments have resulted in Memorandum of Understanding with 28 units and proposed investment of Rs. 14,800 crore...

THE VICE-CHARMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Thank you, Kalita ji. Now, Mr. Girirajan.

SHRI BHUBANESWAR KALITA: Sir, I will take just two more minutes. Sir, I will not go into the technical matters. I do want to raise...

THE VICE-CHARMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): The next speaker is Mr. Girirajan; not present. Shri Dhananjay Mahadik.

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): महादिक जी, आप बोलिए।

श्री धनंजय भीमराव महादिक (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे Union Budget 2025 पर बोलने का जो मौका दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। इसके साथ ही, मैं हमारे नेता

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेन्द्र फडणवीस जी का और सदन के नेता माननीय जे.पी. नड्डा जी का भी आभार प्रकट करता हूं, जिनकी वजह से मैं आज यहां पर खड़ा हूं।

महोदय, संसद में और देश के सामने लगातार आठवीं बार बजट पेश करने के लिए मैं माननीया वित्त मंत्री, निर्मला जी का भी अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। 2025 का यह बजट कोई आम बजट नहीं है। यह 2027 तक देश की अर्थव्यवस्था को 5 trillion economy की ओर ले जाने के लिए एक कदम है और 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' बनाने का जो दृढ़ संकल्प माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी का है, उसकी तरफ एक अहम कदम है। इसके साथ ही साथ, यह देश के 144 करोड़ लोगों की अर्थ शक्ति बढ़ाने वाला, उनके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला तथा उसकी ओर अग्रसर करने वाला बजट है।

सर, कोविड महामारी के बाद दुनिया के कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था बिखर गई, कई सारे प्रधान मंत्री अपने देश की आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पाए, लेकिन यह भारत ही है, जिसकी अर्थव्यवस्था ने माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, 10 साल से लगातार fastest growing economy का रिकॉर्ड बनाए रखा है।

सर, इस देश के बजट का साइज अगर हम 2012-13 की तुलना में देखें, तो 2012-13 में 16 लाख करोड़ का बजट था, जबकि आज यह 2025 का जो बजट है, यह 50 लाख 65 हजार करोड़ का बजट बन गया है। विपक्ष के हमारे कुछ साथी यह कह रहे थे कि इस बजट में मिडल क्लास के लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि इस देश की अर्थव्यवस्था की रीड की हड्डी हैं, लेकिन उपसभाध्यक्ष जी, इस बजट का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को हो रहा है, तो मिडल क्लास को हो रहा है। जब 2014 में हमारी सरकार आई, तब 2.5 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स से माफ किया गया था, हमारी सरकार के फिर आने के बाद 5 लाख, 7 लाख और अब 12 लाख रुपये तक की इनकम को इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है और अगर कोई सैलेरीड पर्सन है, तो 12 लाख, 75 हजार तक उसको कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है।

उपसभाध्यक्ष जी, यह घोषणा एक गेम चेंजर घोषणा है। हमने देखा कि विपक्ष के हमारे कुछ साथी टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देते वक्त बोल रहे थे कि 12 लाख तक का तो ठीक है, लेकिन अगर इनकम 12 लाख, 1 हजार हो जाएगी, तो पूरा 35 प्रतिशत इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कुछ आंकड़े आपके सामने सदन में और देश के सामने रखना चाहता हूं। सर, अगर 12 लाख तक इनकम है, तो उस पर zero tax है; अगर 16 लाख तक इनकम है, तो 7.5 परसेंट इनकम टैक्स लगेगा; अगर 18 लाख तक इनकम है, तो 8.8 परसेंट टैक्स लगेगा; 20 लाख तक इनकम है, तो 10 परसेंट टैक्स लगेगा; 25 लाख इनकम है, तो 13.2 परसेंट टैक्स लगेगा और अगर 50 लाख इनकम है, तो उस पर सिर्फ 21.6 परसेंट टैक्स लगेगा। तो हमारे विपक्ष के साथी जो एक fake narrative set करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी ओर देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, यह 12 लाख तक की इनकम पर जो टैक्स माफ किया है, उससे 8 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को लाभ होगा और राजस्व में हमारी सरकार 1 लाख करोड़ रुपए तक की छूट दे रही है। महोदय, इंसान मेहनत क्यों करता है, कमाता क्यों है? वह इसलिए मेहनत करता है, कमाता है ताकि वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, व्यवसाय में, व्यापार में वृद्धि कर सके, उसके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो,

स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो। मैं यह मानता हूँ कि एक लाख करोड़ रुपए की जो छूट हमारी सरकार दे रही है, यह करोड़ों भारतीयों का सपना पूरा करने का काम करेगा।

महोदय, मैं दो दिनों से विपक्ष के सभी साथियों को सुन रहा था। वे कहते हैं कि इस बजट में कोई विज़न नहीं है, यह बजट निराशाजनक है, किसानों के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। कुछ साथी तो यहाँ तक कह रहे थे कि भाजपा, मोदी सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, क्योंकि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, ये गरीब हैं। मुझे आप बताइए कि अगर 80 करोड़ लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो यह देश कैसे चल रहा है? ये हमारी सरकार को कोसते-कोसते देश की जनता को भी कोस रहे हैं - यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए, उस पर भी हँसी-मजाक उड़ाया जाता है। सर, गरीबों को जो कमाई होती है..., उसको अपने परिवार पर खर्चा करने के लिए जो खर्चा होता है, वह पूरा खर्चा अभी सरकार कर रही है। सरकार राशन दे रही है, मुफ्त गैस दे रही है, शौचालय दे रही है, 4 करोड़ घर बनाए हैं, इसकी वजह से उनकी आय बढ़ी है और इसलिए 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए।

सर, हमारे देश में जो भी निर्माण होता है, उनमें से 80 परसेंट निर्माण एमएसएमई के माध्यम से होता है। जो क्रेडिट गारंटी स्कीम चल रही है, हमारी सरकार ने उसको 5 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 10 करोड़ रुपए कर दिया है, जिसमें अगले पाँच साल में केंद्र सरकार 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ...**(समय की घंटी)**...

सर, मैं एक मिनट में खत्म करता हूँ। स्टार्टअप्स की मर्यादा 10 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 20 करोड़ रुपए कर दी गई है। विपक्ष के लोग बेरोजगारी की बात करते हैं। यह बात सही है कि पिछले 10 सालों में स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ी है, दोगुनी हो चुकी है, जिसकी वजह से पढ़े-लिखे नौजवानों की संख्या बढ़ी है, लेकिन हमारी सरकार इन नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2014 से पहले देश में कई सारी चीजें इंपोर्ट होती थीं, हम इंपोर्ट करते थे, जबकि आज हम भारी मात्रा में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ डिफेंस की बात करें, तो 2014 से पहले 80 परसेंट वस्तुएं इंपोर्ट की जाती थीं, जबकि आज हमारे देश में, जो एचएएल जैसी कंपनी है, मिग, सुखोई, तेजस, ध्रुव, रुद्र जैसे फाइटर प्लेन्स खुद बनाती है। पिछले ही महीने हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ने तीन लड़ाकू जहाजों का इनांगरेशन किया। ...**(समय की घंटी)**... आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी आईएनएस विक्रांत जैसे लड़ाकू जहाज 100 परसेंट हमारे देश में बने हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): श्रीमती साधना सिंह।

श्री धनंजय भीमराव महादिक: सर, हम रोजगार की चिंता पूरी तरह से कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): धन्यवाद। आपको डेढ़ मिनट एक्स्ट्रा मिल गया। अब साधना सिंह जी बोलेंगी, उनकी मेडन स्पीच है। मैडम, कृपया आप बोलिए। ...**(व्यवधान)**... महादिक जी, आपकी जो बची हुई स्पीच है, उसको आप ले कर दीजिए, वह आ जाएगी।

श्रीमती साधना सिंह (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज मुझे यह ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं 2025-26 के बजट पर अपने विचार राज्य सभा के इस प्रतिष्ठित मंच पर रख रही हूँ। महोदय, इस बजट को प्रस्तुत करते हुए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो दिशा- निर्देश दिए हैं, वे देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। यह बजट न केवल हमारे विकास को गति देने वाला है, बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए कई योजनाओं की घोषणा करता है। सबसे पहले मैं मध्यम वर्ग के लिए बजट में किए गए सुधारों की बात करना चाहूँगी। मोदी सरकार ने हमेशा मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास किए हैं और इस बार भी बजट में उन्हें मजबूत करने के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मध्यम वर्ग के सपने जितने बड़े होंगे, राष्ट्र उतना ही बड़ा होगा।

महोदय, आयकर में छूट की सीमा बढ़ा कर उनके लिए सुधार किए गए हैं, इससे आम आदमी का जीवन आसान होगा और उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसानों को लेकर प्रधान मंत्री जी की सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है और इस बजट में भी कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आए हैं। सरकार ने 'किसान सम्मान निधि' के तहत किसानों की मदद बढ़ाने के साथ-साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने की तकनीकी सुधारों की घोषणा की है। साथ ही कृषि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। किसानों के लिए कृषि ऋण की ब्याज दरों में कमी और कृषि उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता के प्रस्ताव से उनका जीवन सरल होगा और वे समृद्ध होंगे।

महोदय, यह बजट शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के अंतर को समाप्त करने की दिशा में एक अहम कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, कृषि क्षेत्र में समृद्धि तथा शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना से देश भर का विकास होगा। सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की है, जिनसे वहाँ के नागरिकों का जीवन-स्तर बेहतर ढंग से बढ़ेगा। प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दूरदृष्टि और नेतृत्व के कारण ही आज भारत ग्लोबल प्लेटफार्म पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मोदी जी की नीतियां न केवल हमारी आंतरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हैं, बल्कि वह इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी एक बेहतर स्थान दिलाती है।

महोदय, यह प्रधान मंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत" की संकल्पना का बजट है। इसमें मजबूती है और इससे हमारा देश आने वाले वर्षों में एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा। वित्त मंत्री जी द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सुधारों की दिशा में कार्य किया गया है। उनकी मेहनत और नीतियों के कारण ही हमारे देश ने वैश्विक मंदी के बावजूद भी अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाए रखा है। वर्ष 2025-26 के बजट में उनके द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णय भारत को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। उनकी नीतियों के कारण मध्यम वर्ग, महिला, युवा, किसान, व्यापारी आदि सभी वर्गों को सहायता प्राप्त होगी। महोदय, यह मोदी सरकार का बजट है और इस सरकार ने एक ऐतिहासिक बजट की ओर अपना एक और कदम आगे बढ़ाया है।

*हर योजना में छुपा समर्पण, देश को नई दिशा दिखाई,
आर्थिक समृद्धि को आधार बना, गरीबों का साथ निभाया,
विपक्ष का विरोध निरर्थक था, देश ने विकास की राह अपनाई।*

महोदय, इस बजट में भारत के समग्र विकास के लिए मोदी सरकार द्वारा एक मजबूत और स्थिर रास्ता तैयार किया गया है। इस बजट का उद्देश्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना, मध्यमवर्गीय सहित सबको साथ लेकर चलना है।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह बताना चाहती हूँ कि विपक्ष दिल्ली से सीखे। दिल्ली की जनता ने हमारे प्रधान मंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया है और विपक्ष को करारा जवाब दिया है। विपक्ष आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी की नीतियों से सीखे और समझे। हमारे मोदी जी देश के लिए देवपुरुष हैं। एक पंक्ति है, जिसको मैं यहां कहना चाहती हूँ:

*जनता के दिल में वही रहता है,
जो जनता के मन की बात करता है,
भारत देश की शान हैं मोदी,
जन-जन की आवाज़ हैं मोदी।*

महोदय, इस अच्छे बजट का हम समर्थन करते हैं, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Shri R. Girirajan, you had missed your turn but since the Chairman has allowed you, you can speak. Will you speak in Tamil?

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, both in English and Tamil.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Okay.

SHRI R. GIRIRAJAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to recall that in 2019 when our hon. Finance Minister presented her Budget, she quoted from *Purananooru* which is an advice to Pandya King, Arivudai Nambi. From 2020, she regularly quoted *Thirukkural* in her Budget Speech. But, this time, in 2025, there is no mention of *Thirukkural* or *Purananooru*. But she quoted one Telugu poet, &“A country is not just its soil, a country is its people.” Does this Government really think about the people? No. They think about some billionaires of this country. One per cent of our population controls 22.6 per cent of the income and wealth is 40.1 per cent.

Sir, our Tamil Nadu Government is contributing 9.04 per cent to the GDP of this country. But what are we getting by way of devolution? It is only 4.8 per cent. The 14th Finance Commission recommended for 42 per cent of tax devolution to

& English translation of the original speech delivered in Telugu.

States. The 15th Finance Commission has reduced it to 41 per cent. But actual devolution is only 32 per cent. I have no jealousy with any other State Government of this country. In this Budget, on 1st February, 2025, after half an hour since the speech began, our hon. Finance Minister, *Tamil magal*, mentioned, four times, about new schemes for Bihar only. But she did not, even a single time, utter the name of Tamil Nadu in the entire Budget.

Sir, the Uttar Pradesh Government is contributing 8.19 per cent to GDP but they are getting devolution of 17.94 per cent. Bihar is contributing 2.7 per cent and getting back devolution of 10.08 per cent. We contribute more and we are not getting proportionate devolution. This is a step-motherly treatment of this Union Government of Tamil Nadu. Hon. Finance Minister, Madam, Tamil Nadu is not just its soil, Tamil Nadu *desam* also have people. Why is this discrimination? Why is this step-motherly treatment? It is because we are Opposition. Despite that, we can say proudly that we are ruling better than this ruling Union Government.

For education, this Union Government's allocation is only 2.5 per cent of total expenditure. But, our Tamil Nadu Government is allocating 13.6 per cent of total expenditure. Regarding the enrolment of students in higher education, the national average is 27 per cent. But, in Tamil Nadu, we have it at 47 per cent even despite the devolution partiality of this Union Government. This Union Government is denying releasing *Samagra Shiksha Abhiyaan* Funds of Rs. 2,152 crore despite several requests made by the State Government of Tamil Nadu. Why is this denial? You are compelling us to sign PM SHRI Scheme, which is imposing Hindi on us. We would not accept. This is a linguistic terrorism imposed on State Government. It is because of this attitude of this Union Government, 40 lakh Tamil Nadu students are suffering now. What was quoted by our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi ji on 11.06.2014 on this in Lok Sabha, I read, "I have experienced first-hand what happens to the State if there is a favourable Government in Delhi and what happens to the State if there is an unfavourable Government in Delhi. I have full experience of this." -- This was told by our by our hon. Prime Minister. He said, "I have experienced the difficulties that the States have to face. How a State is struggling, how a State is neglected, how a State's projects are blocked for personal gains, how conspiracies are headed to prevent the State from developing! I have full experience of this. Therefore, today, a person who understands the problems of the States have been given the opportunity to serve as the Prime Minister of this country. I am the one who knows this pain." It was told by our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi ji. That is why; he assured in the House that they will, definitely, find a solution on this. It was stated by our hon. Prime Minister. He changed his original attitude. No! Still, this

Government has wantonly merged the Railway Budget with Union Budget. But hon. Finance Minister has not uttered Railways anywhere in this Budget. This Budget has not allotted funds for speedy completion of the construction of AIIMS at Madurai in Tamil Nadu. This Budget has not allotted funds for the construction of Greenfield Airport at Parandur in Tamil Nadu. This Budget has not allotted adequate funds to develop road infrastructure on National Highways in Tamil Nadu. This Budget has not allotted funds for expansion of Madurai Airport as well as the establishment of the airports at Vellore, Neyveli. This Budget has never allotted a single *naya paisa* for Tamil Nadu's development. Thank you, Sir.

3.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Shri Madan Rathore.

श्री मदन राठौड़ (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अभी बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के साथियों को सुन रहा था। वर्ष 2014 में जिस समय देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने सत्ता संभाली, उस समय की स्थिति क्या थी और आज क्या स्थिति है, मैं विपक्षी साथियों को वह बताना चाहूंगा। उस समय भ्रष्टाचार चरम पर था और यही नहीं, रात को बैंक खुलवाकर, टेलीफोन करके पैसे उठा दिए गए, तब इस प्रकार की अव्यवस्था थी और पूरी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था थी। उसके बाद देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने जिस तरह संभाला और कितना परिवर्तन आया, यह मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। यूपीए सरकार में फॉरेक्स रिजर्व 304 बिलियन डॉलर था, जो आज 642 बिलियन डॉलर है। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAJEEV SHUKLA): Rathore *Saheb*, will you authenticate it? ...**(Interruptions)**...

श्री मदन राठौड़: सिर्फ यही नहीं, उस समय मुद्रास्फीति 8.2 थी, जो आज 5.2 है।

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): राठौड़ साहब आप authenticate करेंगे।

श्री मदन राठौड़: एफडीआई निर्माण क्षेत्र में 98 मिलियन डॉलर था, अभी 165 मिलियन डॉलर है। ...**(व्यवधान)**...

श्री जयराम रमेश : सर, आप authenticate करने के लिए बोलिए।

श्री मदन राठौड़: सर, इंटरनेट कनेक्शन 25 करोड़ थे...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री राजीव शुक्ला): मदन राठौड़ जी आप इसको authenticate करेंगे। इनका authentication लेना।

श्री मदन राठौड़: जी, सर मैं authenticate कर दूंगा। अभी 97 करोड़ है। यही नहीं, उस समय परमाणु ऊर्जा क्षमता 4,780 मेगावाट थी, अभी 8,180 मेगावाट है। Mobile निर्माण के मामले में उस समय केवल दो इकाई थीं, आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। Export के मामले में 466 बिलियन डॉलर था, जो आज 777 बिलियन डॉलर है। उस समय 387 Medical colleges थे, आज 706 हैं। पिछले 65 वर्षों में 51,348 MBBS सीटें थीं, आज 1,08,940 हैं, यानी पिछले 65 वर्षों में जितनी नहीं थीं, उससे अधिक इन दस वर्षों में कर दी गई हैं। पिछले 65 वर्षों में PG 31,185 seats थीं, लेकिन वर्तमान में 70,645 PG seats बढ़ गई हैं। सर, AIIMS की बात करें, तो पहले केवल सात थे, अभी 23 हो गए हैं। UPA की सरकार में 16 IITs थीं, आज 23 हैं। पहले 13 IIMs थे, आज 21 IIMs हैं।

[उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी) पीठासीन हुईं।]

सर, पहले 676 विश्वविद्यालय थे, आज 1,200 से अधिक, लगभग दोगुने हैं। इन सब परिवर्तनों के बारे में विपक्ष के साथियों को समझने की जरूरत है। पहले 74 airport थे, आज 157 हैं। बहुआयामी गरीबी प्रतिशत भी घटा है। Start-ups की संख्या पहले 350 थी, आज सवा लाख से अधिक है। आप क्या तुलना करेंगे? पहले 15 करोड़ जन-धन खाते थे, आज 50 करोड़ से अधिक हैं। Renewable energy क्षमता पहले 76 गीगावाट थी, आज 203 गीगावाट है। Capital expenditure 2.51 लाख करोड़ था, आज 11.2 लाख करोड़ है। रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में पहले 46 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे, आज 1.3 लाख करोड़ रुपये लगाए जा रहे हैं। सर, पहले पांच शहरों में metro rail थी, आज 20 शहरों में है। राजमार्ग निर्माण की गति पहले 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, आज 28.3 किलोमीटर प्रतिदिन है। विद्युतीकरण की स्थिति 85 प्रतिशत थी, आज 100 प्रतिशत है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले ग्रामीण क्षेत्र में 12 घंटे बिजली मिलती थी, आज 22 घंटे मिल रही है। यह कोई कम बात नहीं है। मोदी जी ने इस देश को बहुत संभाला। उन्होंने किसान की भी चिंता की। आप जानते हैं कि कृषि के मामले में कई जिले पिछड़े हुए हैं। जो कृषि के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, उनमें से हमने 100 जिलों को चुना और उनको चुनकर उनमें मृदा का परीक्षण करेंगे। जमीन से सात-आठ इंच नीचे की मिट्टी लेकर उसका परीक्षण करवाकर वहां पर किस प्रकार की फसल हो सकती है, किस प्रकार का उन्नत बीज दिया जा सकता है, ऐसा करके उन जिलों को समृद्ध करेंगे। उत्पादन के क्षेत्र में उसको मजबूत करेंगे और उसके बाद 100 जिले लेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मोदी जी ने दी है, यह विपक्षी साथियों को समझने की जरूरत है। विरोध करना ठीक है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और आप अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन यह परिवर्तन जो आया है, इससे खुश होना चाहिए, इसको उनको समझने की जरूरत है। यही नहीं, उन्होंने फसल बुआई से लेकर मंडी तक चले जाने तक फसल बीमा दिया। तब तक हर इश्यू पर कभी भी कोई दुर्घटना हो जाए, आपदा आ जाए, तब भी उस किसान की फसल बीमित है। यही नहीं, Enam योजना दी।

National Agriculture Market, किसान अपनी फसल को मंडी में registration करवाने के बाद हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में अपनी फसल बेच सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था दी, ऋण सुविधा दी, क्योंकि एक-साथ फसल मार्केट में आती है, तो भाव घट जाते हैं। उस फसल को गोदाम में रखने के बाद वह कहीं भी बेच सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख रुपये किया, एमएसपी बढ़ाई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया। इतना ही नहीं, सब्जियों और फल उत्पादन के क्षेत्र में भी काम किया। मैं रेल मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे गंगानगर में किन्नू बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ था और बंगाल में भेजने के लिए हमने उनसे रेलगाड़ी मांगी थी, जो उनके द्वारा तत्काल दे दी गई, ताकि वहाँ बंगाल के और लोगों को भी किन्नू मिल सके। उन्होंने हमें इस प्रकार की व्यवस्था दी, यानी द्रुत गति से फसल को कैसे और खराब नहीं होने दे, वह मार्केट में तत्काल पहुंचाया जा सके, ताकि किसान को उसका भाव मिले, इस पर तत्काल काम किया।

महोदया, यही नहीं लंबे रेसे वाले कपास के उत्पादन के क्षेत्र के लिए मैं सोचता हूँ कि यदि इस प्रकार का कपास पैदा किया गया, तो यह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वस्त्र उद्योग के लिए वरदान साबित होगा। महोदया, यूरिया संयंत्र भी लगाया गया। ...**(समय की घंटी)**...

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): माननीय सदस्य, कृपया कन्क्लूड कीजिए।

श्री मदन राठौड़: महोदया, एमएसएमई में भी डबल किया, एमएसएमई को भी मजबूत करने की कोशिश की, क्रेडिट गारंटी दी, नया स्टार्ट-अप दिया और राशि को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये तक देने का प्रावधान भी किया।

महोदया, यद्यपि समय बहुत कम मिला है, लेकिन फिर भी ठीक है। आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया है, इसके आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): माननीय सदस्य आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री रामेश्वर तेली जी, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

श्री रामेश्वर तेली (असम): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं अपनी बात अपनी मातृभाषा असमिया में कहना चाहता हूँ। & Our Finance Minister, Nirmala Sitharaman ji, presented the 2025-26 budget. I fully support this Budget and would like to share my thoughts on it. Nirmala Sitharaman ji is the only Finance Minister and the only woman to have presented the budget eight times. I would like to thank the Finance Minister. There are still many speakers who wish to address this Budget; so, I will keep my remarks brief. This Budget has been prepared with significant consideration prior to its presentation. There is one topic in particular that resonates with me, and I felt compelled to speak about it, even if just for a couple of minutes. As a former Member

& English translation of the original speech delivered in Assamese.

of Parliament from the Dibrugarh district, Lok Sabha, I received numerous requests from people and organizations regarding the Namrup Fertilizer Factory. During my ten years in office, I raised this issue in Parliament several times, but unfortunately, it did not come to fruition.

In the 2025-26 Budget, the Namrup fertilizer factory has been mentioned, and I am delighted that a fertilizer factory will be established in Namrup with an annual capacity of 12.7 metric tons. I would like to express my gratitude to our Prime Minister, Shri Narendra Modi, and to the Minister of Fertilizers, J.P. Nadda. I also extend my thanks to Finance Minister, Smt. Nirmala Sitharaman and to our popular Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma. It is through the efforts of Dr. Himanta Biswa Sarma that the Namrup Fertilizer Factory has become a reality. I would like to inform this August House that the Assam Government will hold a 40% share in the Namrup Fertilizer Factory. Therefore, I would like to thank all four of these remarkable leaders through this House.

During the Budget discussion, many comments were made and the Opposition also voiced several negative statements. One speaker from the Opposition mentioned that cockroaches can be found in the food served on trains, questioning how the railway system can operate under such conditions. Perhaps he was referring to the issues that existed during the Congress period. However, I am not sure if he has boarded a train recently, because we now have trains like Vande Bharat. I encourage the Member of Parliament to experience a ride on the Vande Bharat train to understand the quality and efficiency it offers.

Currently, the Union Government, along with the Railways Department, is actively working on Assam's railway project and significant progress has been made. In Assam, electrification is also underway, and many new trains are being introduced. I would like to express my gratitude to our Rail Minister for these developments. In this Budget, the Kisan Credit Card has been mentioned as well. Previously, it provided a loan limit of 3 lakhs Rupees, which has now been increased to 5 lakhs Rupees. This change will benefit our farmers, and we will place greater emphasis on farming in Assam. The Kisan Credit Card will indeed be advantageous for our agricultural community. Additionally, individuals earning a salary who previously paid taxes will now receive tax benefits of up to 12 lakhs per annum. Many beneficial provisions have been included in this Budget, and I would like to thank our Finance Minister once again for these initiatives. Furthermore, the Budget states that 80 crore people will receive free rations. Numerous other positive measures are also outlined in this Budget. In support of this Budget, I extend my gratitude to the Finance Minister, and with that, I conclude my speech.

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): सुश्री कविता पाटीदार जी।

सुश्री कविता पाटीदार (मध्य प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदया, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सर्वप्रथम हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण जी को इस उद्देशीय और सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने वाले बजट को रखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि इस देश के 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पंख देने वाली एक युगांतकारी पहल है। माननीय प्रधान मंत्री जी की वह प्रतिबद्धता है, जो आज वादों से आगे निकलकर जमीनी हकीकत पर आधारित है। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बजट को समृद्धि का गुणक बताया है, जो बचत, निवेश और विकास के मार्ग को प्रशस्त करेगा। आज इस बजट को देखते हुए, मुझे बाबा साहेब डा. अम्बेडकर जी का स्मरण हो रहा है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के महू की बेटा हूँ। वह महू, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जन्म स्थली है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पंच तीर्थों का निर्माण किया गया है, वह जन्म तीर्थ उनमें से एक है। मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष है कि उस तीर्थ के निर्माण के बाद प्रधान मंत्री के रूप में पहले प्रधान मंत्री, जिन्होंने वहाँ पर माथा टेका, वे नरेन्द्र मोदी जी हैं। उन्होंने सिर्फ माथा नहीं टेका, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दी हुई सीख को आत्मसात करते हुए, उसे पूरा करने का संकल्प लिया। बाबा साहेब ने पूरी दुनिया को समरसता का संदेश दिया और माननीय प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास करके प्रत्येक वर्ग की प्रगति को सुनिश्चित करने का काम किया।

माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मुझे यह बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि काँग्रेस के लोग, जिन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया, उन्हें हराने का काम किया, वे आज महू की उस धरा पर राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पहुंचते हैं और वे महू की उस जनता को, महू की उस पवित्र भूमि को कलंकित करने का काम करते हैं। यह कहना कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती, तो महोदया, मैं यह बताना चाहती हूँ कि सालों तक सत्ता पर रहने वाली काँग्रेस को यह नहीं पता है कि गरीबी दूर कैसे होती है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, माननीय मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है कि गरीबी दूर कैसे होती है। उन्हीं के सुशासन का परिणाम है कि आज 25 करोड़ जनता गरीबी रेखा से बाहर आई है। आज हर एक व्यक्ति के सिर पर छत है। हर घर में नल है और नल में जल है। आज हर गांव तक सड़क बनी हुई है। जब रेल की बात आती है, तो मैं मध्य प्रदेश के संबंध में कुछ कहना चाहूंगी। 2014 से पहले के बजट की तुलना में आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 23 गुना ज्यादा बजट बढ़ाकर मध्य प्रदेश को रेलवे में दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहती हूँ। आज मध्य प्रदेश में मेडिकल की 2,000 नई सीट्स के साथ पूरे देश में 75,000 नई मेडिकल सीट्स देकर युवाओं को पढ़ने के लिए शिक्षा के नए अवसर प्रदान करने का काम माननीय माननीय मोदी जी ने किया है। इतना ही नहीं, जब आर्थिक तंगी के कारण सांसे थम जाती थीं, उन्हें जीवन देने का काम भी अगर किसी ने किया है, तो आदरणीय मोदी जी ने आयुष्मान जैसी योजना देकर किया है। मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व है कि 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की जीवन रक्षक

दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाकर आदरणीय मोदी जी ने यह बता दिया है कि 'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।' इसके लिए भी मैं माननीय मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

महोदया, मैं खुद किसान पुत्री हूँ और हम सब जानते हैं कि किसानों को विपक्ष ने हमेशा चुनावी घोषणा का पात्र समझा है, जबकि माननीय मोदी जी ने किसान को हमेशा भारतीय विकास के एजेंडे के केंद्र में रखा है। आज किसान सम्मान निधि के साथ, प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के साथ, दलहनों में आत्मनिर्भरता बनाने के साथ, क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया है और कृषि लाभ का धंधा कैसे बने, यह दुनिया को बता दिया है।

आज महिला होने के नाते मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि आर्थिक गतिविधियों में 70 प्रतिशत योगदान महिलाओं को देकर उन्होंने आज यह सिद्ध कर दिया है कि माननीय मोदी जी के सुशासन में आज बेटियां फाइटर प्लेन भी चला रही हैं और आने वाले समय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे अभूतपूर्व निर्णयों के द्वारा इस देश के नेतृत्व में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित होगी।

मैं माननीय मोदी जी को कोटि-कोटि धन्यवाद इस बात के लिए भी देती हूँ कि जब माननीय निर्मला सीतारमण जी ने इस पूरे देश के सामने बजट प्रस्तुत किया, तो मध्यमवर्गीय परिवारों के चेहरों पर खुशियां लाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। बजट में 12 लाख रुपये तक की आय को कर से छूट प्रदान की है। हम लोग हमेशा मांग करते हैं कि सर्वप्रथम हम लोगों के जीवन में खुशियां जो लाए, ऐसी गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति चाहता है, तो माननीय मोदी जी ने उस बात को परिलक्षित किया है। ...(समय की घंटी)... आज विकास भी है, तो विरासत भी है।

मैं इतना कहना चाहती हूँ कि महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ते हुए आज हमारे माननीय मोदी जी के कदमों से हमने यह दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तीसरी जो पारी है, यह उसकी शुरुआत है और आगे बहुत कुछ बाकी है। आगे सारा विश्व मोदी जी के नेतृत्व में इस भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखेगा। इस संकल्प के साथ पुनः बहुत-बहुत बधाई देती हूँ। जय हिंद! जय भारत!

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): धन्यवाद। श्री रामदास अठावले जी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): आदरणीय मैडम:

*2025-26 का यह नहीं है खाली बजट,
यह तो है नरेन्द्र मोदी जी के विकास का आईना,
यह बजट सुनकर परेशान हो जाएगा चाइना,
माननीय खरगे जी, मत छोड़ो नरेन्द्र मोदी जी के नैना,
नहीं तो 2029 में भी हो जाएगी आपकी दैना
इस बजट से खुश है मैंन कॉमन,
क्योंकि अच्छा बजट देने वाली अर्थमंत्री हैं निर्मला सीतारमण,
इस बजट से अब देश में रहेगा अमन,*

क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं हमारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण,
 अब तो टूट रहा है विपक्षी दल,
 मोदी जी के हाथ में ही होगा कल,
 पहुंच रहा है घर-घर में नल से जल,
 मोदी जी ही निकाल सकते हैं समस्या का हल।

आदरणीया मैडम, यह जो बजट है, यह बजट सामाजिक न्याय के साथ-साथ आर्थिक न्याय देने वाला बजट है। यह बजट नीचे के आदमी, मिडल आदमी और ऊपर के भी आदमी, सबके लिए है। यह जो बजट है, यह बजट चाहे बीजेपी का आदमी हो, कांग्रेस का आदमी हो, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी हो, सबके लिए है। यह मध्य प्रदेश के लिए भी है, कर्नाटक के लिए भी है, वेस्ट बंगाल के लिए भी है, असम के लिए भी है, हमारे महाराष्ट्र के लिए भी है। यह बजट इतना important है कि इस बजट में सभी वर्गों को न्याय देने की कोशिश हुई है। इसीलिए:

इस बजट से जाग गई है गाँव-गाँव की गली,
 बिना मतलब मत उड़ाओ हमारे बजट की खिल्ली।
 इस बजट से मोदी जी की हो रही है सारे देश में बल्ली-बल्ली,
 विरोधी दलों की टूट रही है कली-कली।
 जो नेता होता है विकासवादी,
 उनका नाम है नरेन्द्र मोदी।
 पूरे देश की बोल रही है दादी,
 ब हुत ही अच्छे हैं प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी।

मैडम, यह जो बजट है, इस बजट में सभी मंत्रालयों को बहुत ही अच्छा बजट दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के लिए 6,81,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के लिए 2,87,000 करोड़ का बजट है; रेलवे के लिए 2,55,000 का बजट है; गृह मंत्रालय के लिए 2,33,000 करोड़ का बजट है; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के लिए 2,15,000 करोड़ का बजट है। जो मेरा मंत्रालय है - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, वह सभी लोगों को न्याय देता है। जो हमारे पास आते हैं, हम उनको न्याय देते हैं और जो नहीं आता है, उनको नहीं देते हैं। जिनको न्याय चाहिए, वे हमारे पास आते हैं। मेरे मंत्रालय, Social Justice and Empowerment Ministry का बजट 1,68,478 करोड़, इतना बड़ा बजट है। ट्राइबल का 1,29,250 करोड़ का बजट है। दलित हो, आदिवासी हो, नरेन्द्र मोदी जी का ध्यान सबकी तरफ होता है। नरेन्द्र मोदी जी सबको देखते हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने सभी लोगों का आह्वान किया है कि आइए, हमारे साथ आइए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब लोग मिल कर देश को आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान का भारत बनाना है, तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाई थी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने नदी जोड़ने का प्रोग्राम announce किया था। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी Water Resources Minister थे, तब आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधान मंत्री थे, ...**(समय की घंटी)**...

उस समय नदी को जोड़ने का प्रोग्राम बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया था। डैम बनाने का प्रोग्राम भी बाबा साहेब ने बनाया था। डैम से बिजली का निर्माण होता है, डैम से पीने के लिए पानी मिलता है, खेती के लिए पानी मिलता है। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए देश को मजबूत करने के लिए हम सब लोगों को मिल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा के लिए 1,08,000 करोड़ का बजट है, संचार के लिए 99,000 करोड़ का बजट है, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए 99,000 करोड़ का बजट है, जल शक्ति के लिए 96,000 करोड़ का बजट है। मुझे लगता है कि देश भर में 10 सालों में जनधन योजना के 51 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खुले हैं और मुद्रा योजना में कम से कम 56 करोड़ लोगों को लोन मिला है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): आप conclude करिए, प्लीज।

श्री रामदास अठावले: उसके साथ-साथ, जो हमारी उज्वला योजना है, उसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस का सिलिंडर मिला है। 4 करोड़ लोगों को आवास भी मिला है, गरीबों को पक्का मकान मिला है और 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों में शौचालय पहुंचा है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): थैंक यू।

श्री रामदास अठावले: ये सब काम हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में आपने काम किया है। आदरणीय सोनिया जी इधर आई हैं। मैं भी आपके साथ रहा हूं। मैं कई साल आपके साथ रहा हूं। आज मैं नरेन्द्र मोदी जी के साथ हूं और मैं अभी इधर ही रहने वाला हूं, उधर आने का विषय नहीं है। नरेन्द्र मोदी जी का यह जो बजट है, निर्मला सीतारमण जी ने यह जो बजट दिया है, यह बजट बहुत ही स्ट्रॉंग बजट है, बहुत ही एक्टिव बजट है।

उपसभाध्यक्ष (श्रीमती किरण चौधरी): धन्यवाद, धन्यवाद।

श्री रामदास अठावले: निर्मला जी हमारी महिला अर्थ मंत्री हैं। माननीय नरेन्द्र मोदी जी सबको न्याय देते हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने दलित समाज का राष्ट्रपति बनाया, उन्होंने आदिवासी समाज का राष्ट्रपति बनाया। नरेन्द्र मोदी साहब ने मुझे भी मंत्री बनाया। ...**(समय की घंटी)**... मेरी पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी का, एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ...**(व्यवधान)**...

(सभापति महोदय पीठासीन हुए।)

आदरणीय सभापति जी, मेरी पार्टी का एक भी पार्लियामेंट मेंबर नहीं है, उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे मंत्री बनाया है। मैं तीसरी बार मंत्री बना हूं। ...**(व्यवधान)**... मैं तीसरी बार मंत्री बना हूं, आप तो पहली बार मंत्री बने हैं। मुझे तीन बार मंत्री बनने का मौका मिला है। मोदी साहब, बाबा साहेब को मानते हैं। उन्होंने बाबा साहेब के सभी काम पूरे किए हैं। उनके लिए जितना भी बजट चाहिए, उतना बजट उन्होंने दिया है। महोदय, मुम्बई में बाबा साहेब अंबेडकर जी का एक मेमोरियल बन रहा है। वहां इंदू मिल में कम से कम 1,200 करोड़ से ज्यादा का मेमोरियल बन रहा

है। वहां बाबा साहेब का स्टैच्यू 350 फीट का है। इस प्रकार, बाबा साहेब अंबेडकर जी का जो vision है, उसको जरूर पूरा करने के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं और इसीलिए मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। हम लोग एनडीए को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सीटें जरूर कम आई हैं, लेकिन अगर इस वक्त कम सीटें आई हैं, तो अगली बार हम 400 तक पहुंचेंगे, आपकी सीटें कम होती जाएंगी और हमारी सीटें बढ़ती जाएंगी। हम देश को विकास की दिशा में आगे ले जाने वाले हैं। यह जो बजट है, यह बहुत बड़े सामाजिक न्याय का बजट है और इसीलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बजट!

**CORRIGENDUM TO APPENDIX-V TO THE REPORT OF THE JOINT COMMITTEE
ON THE WAQF (AMENDMENT) BILL, 2024**

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, Papers to be laid on the Table. Corrigendum to Appendix-V to the Report of the Joint Committee on the Waqf (Amendment) Bill, 2024 -- Dr. Medha Vishram Kulkarni.

DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI (Maharashtra): Sir, I lay on the Table, a copy (in English only) of corrigendum to Appendix-V to the Report[%] of the Joint Committee on the Waqf (Amendment) Bill, 2024.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, this shows that the Minister had misled the House. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, it shows that parliamentary institutions are blossoming, sentiments are taken into consideration and steps are taken. And, this gives us another message — we must take recourse to law rather than engage in something which people cannot approve, or is to their distaste. If we have anything to add on this, it is appreciation, and we want more of such things to happen because it is only through exchange by dialogue that things happen.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, it is only because of our pressure that the corrigendum was presented. I would like the Leader of the House to accept this. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I express my gratitude to the Government because the matter was brought to my notice ...*(Interruptions)*...

[%] The Report was laid on the Table of the Rajya Sabha today, the 13th February, 2025.